।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5
● अंक-249
रायपुर, गुरुवार
04 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

पेज-8› खेती केवल आजीविका नहीं...

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

भारत में बदले विदेशियों के वीजा नियम

नईदिल्ली। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए अब घड़ी की सुइयां बदल चुकी है। अगर कोई जानने वाला एक दिन भी बिना जानकारी के भारत में रुका तो उसे भारी कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने रातोंरात इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 लागू कर दिया है। अब 180 दिन वाला वो पुराना ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है। दरअसल भारत हमेशा से अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए जाना जाता है। लेकिन बदलती सुरक्षा चुनौतियों और प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लक्ष्य के साथ गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन नियमों में बड़े संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य देश में रह रहे विदेशी नागरिकों का सटीक डाटा रखना और किसी भी प्रकार के अवैध प्रवास को रोकना है। देखिए अब तक नियम यह था कि अगर कोई विदेशी 180 दिन से ज्यादा रुकता था तो उसे अतिरिक्त 14 दिन मिलते थे। लेकिन अब इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 के तहत प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

अगर आपका वीजा 180 दिन का है और आपको लगता है कि आपको 181वें दिन भी भारत में रहना है तो आपको वो 180 दिन खत्म होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे बड़ी बात है कोई ग्रेस पीरियड नहीं। जी हां, अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि समय खत्म होने के बाद हम फॉर्म भर देंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के भीतर सूचना देना अब आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। तीसरा मुख्य बिंदु है लंबी अवधि के वीजा पर भी लगाम। जिनके पास 1 साल या 5 साल का वीजा है उनके लिए भी नियम काफी सख्त हैं। अगर वे 1 साल में 180 दिन से ज्यादा भारत में बिता रहे हैं तो उन्हें हर हाल में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। वैसे इस कानून में एक बहुत ही भावुक और तकनीकी पहलू भी जुड़ा हुआ है जो उन बच्चों से जुड़ा है जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन माता-पिता में कोई एक विदेशी है। इतना नहीं भारतीय माता-पिता को राहत है। अगर माता-पिता में से एक भारतीय है और वे चाहते हैं कि बच्चा भारतीय नागरिक ही बना रहे, तो उन्हें जन्म के 30 दिनों के भीतर वीजा या एग्जिट परमिट के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। और यह एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा एक और अन्य बिंदु है दोहरी नागरिकता की स्थिति। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा होकर या किसी भी समय किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो इसकी जानकारी 30 दिनों के भीतर सरकार को देनी होगी और ऐसा ना करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

यह नियम केवल विदेशियों पर ही नहीं बल्कि उन्हें सेवाएं देने वाले संस्थाओं पर भी लागू होता है। भारत में इलाज कराने आने वाले विदेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां भर्ती हर विदेशी नागरिक की सटीक जानकारी सरकार को दें। अगर कोई संस्थान अगर यह जानकारी छुपाता है तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार अब हर उस जगह का रिकॉर्ड चाहती है जहां कोई विदेशी नागरिक ठहरा है या खुद को दिखाने जा रहा है? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह कदम सुरक्षा के लिए है? एक्सपर्टों का साफ कहना है कि इन नियमों से ना केवल आंतरिक सुरक्षा काफी मजबूत हो जाएगी बल्कि इमीग्रेशन की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो जाएगी। गृह मंत्रालय अब एक क्लिक पर जान सकेगा कि किस राज्य में कितने विदेशी अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय से रह रहे हैं और इन सख्त नियमों से उन लोगों की पहचान करना काफी आसान हो जाएगा जो टूरिस्ट वीजा पर आकर यहां अवैध रूप से बस जाते हैं।

सेवा-सेतु केन्द्र से सुशासन को मिली नई रफ्तार

अब सरकारी सेवाएं मोबाइल की स्क्रीन पर

रायपुर। सरकारी कार्यालयों के चक्कर, लंबी कतारें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव से होने वाली परेशानियां अब धीरे-धीरे अतीत की बात बनती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में सेवा-सेतु केन्द्रों के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों तक सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप में पहुंचाने की पहल ने सुशासन को नई पहचान दी है। अब प्रदेश के नागरिक 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त कर रहे हैं।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहजता है। सेवा-सेतु केन्द्रों में लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही नागरिकों को उपलब्ध सभी सेवाओं की सूची और प्रत्येक सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। इससे लोगों का समय बच रहा है और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो रही है।

डिजिटल सुविधा को और व्यापक बनाते हुए राज्य सरकार ने वॉट्सऐप आधारित सेवा प्रणाली भी शुरू की है। अब नागरिक एक निर्धारित वॉट्सऐप नंबर पर संदेश भेजकर आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-नकल तथा नाम परिवर्तन से संबंधित सेवाओं सहित सैकड़ों शासकीय सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सेवा-सेतु केन्द्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। इससे कम शिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक स्थानीय भाषा

तथा वॉयस कमांड के माध्यम से भी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती दे रही है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुख बना रही है। सेवा-सेतु केन्द्र आज तकनीक आधारित सुशासन के सशक्त प्रतीक बनकर उभर रहे हैं।

कर्नाटक में शिवकुमार सरकार का आगाज

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में चल रहा सियासी घमासान बुधवार को डी.के. शिवकुमार के सीएम पद की शपथ लेते ही थम गया। आठ बार के विधायक और कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक का नया सीएम बनने पर बधाई दी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सीएम को शुभकामाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाथ में संविधान की प्रति लिए शिवकुमार को शपथ दिलाई। उनके साथ वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर ने डिप्टी सीएम और 12 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।

कोलकाता के मेयर हकीम ने पद से दे दिया इस्तीफा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि, इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायको ने अलग गुट बना लिया है। जिसे विधानसभा स्पीकर की ओर से मंजरी भी दे दी गई है।

फिरहाद हकीम टीएमसी के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी से मेयर पद छोड़ने की अनुमति मांगी थी। उस समय पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। लेकिन बुधवार को उन्होंने दोबारा इस्तीफे की इच्छा जताई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इसकी मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतों के कारण उन्होंने यह फैसला लिया।

टीएमसी के लिए बड़ा झटका है?

फिरहाद हकीम लंबे समय से टीएमसी का बड़ा चेहरा रहे हैं। वह अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पार्टी की मजबूत पकड़ माने जाते हैं। 2018 से वह कोलकाता के मेयर पद पर थे और राज्य सरकार में कई अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब टीएमसी पहले से ही बगावत और संगठनात्मक संकट से जूझ रही है।

हाल के दिनों में कोलकाता नगर निगम के कई पार्षद भी इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के भीतर लगातार असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कई नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इससे टीएमसी की अंदरूनी स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी के सामने संगठन को बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा सरकार बनने के बाद बदले हालात?

कुणाल घोष के मुताबिक, फिरहाद हकीम ने भाजपा सरकार बनने के बाद कामकाज में कठिनाइयों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल तेजी से बदला है। कई टीएमसी नेताओं का कहना है कि सरकार बदलने के बाद विपक्षी नेताओं के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खारिज करती रही है।

प्रमुख समाचार

गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी की संभावित कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राज्य सीआईडी द्वारा टीएमसी विधायकों के कथित हस्ताक्षर जालसाजी की जांच के संबंध में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। यह जांच दो विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में की गई शिकायत पर आधारित है। विधायकों ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के उस प्रस्ताव में उनके हस्ताक्षर जाली किए गए थे, जिसमें बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त करने का प्रस्ताव था। विधानसभा सचिवालय ने टीएमसी के निलंबित विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायत पर कोलकाता पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में, राज्य के गृह सचिव ने जांच सीआईडी को स्थानांतरित कर दी थी।

ममता का प्रदर्शन फ्लॉप, कोई साथ नहीं : दिलीप घोष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अध्यक्ष ममता बनर्जी के पार्टी सांसदों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों के विरोध में किए गए प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदर्शन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था और यह लोगों में बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए घोष ने कहा कि न तो जनता यह चाहती है और न ही उनकी पार्टी के लोग। इसीलिए कोई उनके साथ नहीं आया। जनता ने अपना जनादेश दिया है। जनता ने बहुत कुछ सहा है। ममता बनर्जी ने रानी रश्मोनी एवेन्यू पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पार्टी द्वारा चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित घटनाओं में अपने नेताओं पर लक्षित हमलों का विरोध किया। प्रदर्शन शुरू करने से पहले, बनर्जी ने कोलकाता में भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ डोला सेन और कल्याण बनर्जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उन्हें भारत के संविधान की एक प्रति लिए हुए देखा गया।

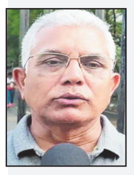

इंडिया गठबंधन फेल, इसमें दम नहीं : ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आगामी इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए इसे संयुक्त क्षेत्रीय प्रभाव की कमी के कारण विफल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है, उसमें कोई ताकत नहीं है। ममता बनर्जी के पास उत्तर प्रदेश में वोट नहीं हैं, कांग्रेस के पास वोट नहीं हैं। उस गठबंधन में शामिल सभी लोगों का अलग-अलग राज्यों में अपना दबदबा है। अब, अगर वे सब एक साथ आकर सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़ें, तो वे कितनी ताकत जुटा पाएंगे? इसीलिए इंडिया गठबंधन असफल है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक के नेता 8 जून को राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के भाग लेने की उम्मीद है। यह बैठक मई में संपन्न हुए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद हो रही है।

ठेका घोटाला : कांग्रेस ने सीएम पेमा खांडू पर लगाए आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में मनमानी करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन सभी फाइलों पर नियंत्रण रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीबीआई जांच का हिस्सा होनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकों के तरजीही आवंटन के आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये ठेके मुख्यमंत्री खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली या उनसे संबंधित कंपनियों को दिए गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि खांडू के मामले में भाजपा ने सभी सिद्धांतों और मानदंडों को त्याग दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। रमेश ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से वहां के मुख्यमंत्री के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिए। इसके बावजूद, भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में बेशर्मी से काम लेने का स्पष्ट फैसला लिया है।

केरल विधानसभा में तबादलों को लेकर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में बुधवार को कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद राजनीतिक बदले की भावना से तबादले किए जा रहे हैं और पोस्टिंग प्रक्रिया पर बिचौलियों व सत्ता से जुड़े लोगों का प्रभाव है। सीपीआई (एम) विधायक वी जॉय ने सदन में कहा कि बिना तय मानकों का पालन किए तबादले किए जा रहे हैं और पसंदीदा लोगों को मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 33 विभागों में 207 तबादला आदेश जारी किए गए हैं, जिनसे 2,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। हालांकि, राज्य मंत्री सनी जोसेफ ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी तबादले निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मई में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से रिक्तियां पैदा होती हैं, जिसके कारण विभिन्न विभागों में तबादले स्वाभाविक रूप से होते हैं।

भाग 2

देश की सबसे बड़ी समस्या डेमोग्राफी परिवर्तन के खिलाफ केन्द्र की मुहिम

अभिनय आकाश

गंताक से आगे

दूसरा गृह मंत्रालय के पास एक और स्पेसिफिक रिपोर्ट है ये कि वेस्टर्न बाउंड्रीज में और ईस्ट में भी खास करके बंगाल में भी जो ड्रग्स का सारा कारोबार चल रहा है वो जो 15 किमी जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वो एक पड़ाव है। जैसे पाकिस्तान से किसी ने फेंका ड्रग्स पंजाब कि बाउंड्री में किसी ने फेंका। उसे कलेक्टर कर 15 किलोमीटर के अंदर और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गृह मंत्रालय ने एक आर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है उसको तुरंत तोड़ा जाए। कुल 50 बीएसएफ के बॉर्डर से बीएसएफ जहां तैनात है वहां से 50 किमी तक पूरी पैनी नजर और हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट डिटेन और डिपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया। टारगेट पर अवैध घुसपैठिए बताए गए। नतीजा बंगाल के बॉर्डर्स पर दिख रहा है। शुभेंदु अवैध घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के पहले से उठाते रहे हैं। सिर्फ शुभेंदु नहीं बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ का मुद्दा अपनी लगभग हर चुनावी रैली में हर सभा में उठाया है। इस चुनाव ही नहीं 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठ को लेकर तीखे बयान देखने को मिले थे।

सितंबर 2018 में बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक बताया था और कहा था कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने एक रैली में कहा था कि ये लोग गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं। हमारी नौकरियां ले रहे हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। पर बीजेपी सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ही नहीं रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी मुखर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस मुद्दे को एक ऐसी चुनौती के रूप में देखता रहा है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है। 5 अक्टूबर 2022 को विजय दशमी पर सर संघ संचालक मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन की वजह से देशों का बंटवारा हुआ है और इसके पीछे धर्म परिवर्तन

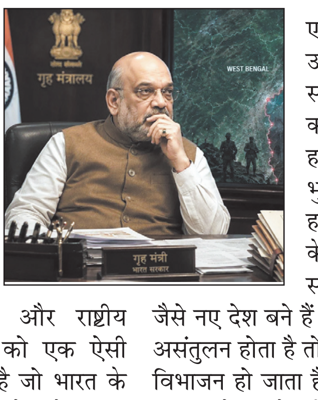

एक बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 50 साल पहले जब जनसंख्या का असंतुलन हुआ था तब हमें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े थे। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ। आज के समय में ईस्ट तिमोर, साउथ सूडान और कोसोवो जैसे नए देश बने हैं। इसलिए जब जनसंख्या में असंतुलन होता है तो नए देश बनते हैं। देशों का विभाजन हो जाता है।

इससे पहले भी आरएसएस के बड़े नेता जनसंख्या में अपने हिसाब से एक संतुलन की बातें करते आए हैं। पूर्व आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने 2005 में कहा था कि परिवारों में तीन से कम बच्चे नहीं होने चाहिए।

घुसपैठ को लेकर क्या-क्या बातें सामने आई

आजादी के बाद से देखते हैं घुसपैठ को लेकर क्या-क्या बातें सामने आई। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल ने अपनी एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि 1948 से 1961 के बीच करीब 31 लाख लोग जिनमें ज्यादातर हिंदू थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। उस समय असम के मुख्यमंत्री बीपी वाली ने बताया था कि जनवरी 1964 से जनवरी 1965 के बीच करीब 1.8 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से असम पहुंचे हुए थे। 1997 में तब के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने तब कहा था कि भारत में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यह इस तरह का पहला आधिकारिक बयान माना गया था। इंडिया टुडे मैगजीन ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कुछ आंकड़े छापे थे। तब के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 54 लाख, असम में 40 लाख, त्रिपुरा में 8 लाख, बिहार में 5 लाख, महाराष्ट्र में 5 लाख, राजस्थान में 5 लाख और दिल्ली में 3 लाख अवैध प्रवासी बताए गए थे। इन सभी को मिलाकर कुल संख्या करीब 1 करोड़ 8,300 के आसपास बैठ रही थी। 2001 में माधव गोडबोले की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह आंकड़ा और बढ़ा हुआ दिखता है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 1.5 करोड़ बताई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हर महीने लगभग 3 लाख लोग अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं।

गोबरा नवापारा नगर में सुशासन तिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन

पेयजल समस्या पर महिलाओं ने मटकी फोड़कर जताई नाराजगी

अवैध रेत परिवहन और शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग

अभनपुर। गोबरा नवापारा नगर में व्याप्त विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेसियों और स्थानीय महिलाओं ने नगर के हरिहर स्कूल में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां और खाली मटकी लेकर पहुंचीं और पेयजल संकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नगर में अवैध रेत और अन्य खनिजों का परिवहन धड़ल्ले से जारी है। अवैध शराब बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रही है। गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही, लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं और नागरिकों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पानी की समस्या के विरोध में खाली मटकी आयोजन स्थल पर पटककर फोड़ दी। इससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद, जनविरोधी नीतियां बंद करो और जनता को मूलभूत सुविधाएं दो जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मौके पर पहुंचे अभनपुर एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों को सुना और संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया।

आम जनता पर कार्रवाई आंगनबाड़ी केंद्रों में खुद मोटर पंप लगा रही नगर पालिका

नियमों पर उठे सवाल - आम जनता पर कार्रवाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में खुद मोटर पंप लगा रही नगर पालिका

महासमुंद। नगर पालिका महासमुंद में नियमों के पालन को लेकर दोहरे मापदंड का मामला सामने आया है। एक ओर जहां नगर पालिका आम नागरिकों द्वारा नल कनेक्शन में मोटर पंप लगाने पर कार्रवाई करती है, वहीं दूसरी ओर शासकीय आंगनबाड़ी केंद्रों में खुद नगर पालिका द्वारा नल कनेक्शन पर मोटर पंप लगाकर पानी की व्यवस्था किए जाने का मामला उजागर हुआ है। अब सवाल उठ रहे कि आखिर जब नियम सबके लिए समान हैं तो यह अलग व्यवस्था क्यों?

महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र के 30 वार्डों में करीब 80 हजार की आबादी निवास करती है। नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका ने घर-घर नल कनेक्शन दिए हैं और इसके एवज में जलकर भी वसूला जाता है। गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने पर कई लोग नल कनेक्शन में मोटर पंप लगाकर पानी खींचते हैं, जिससे आसपास के घरों में जलापूर्ति प्रभावित होती है। इसी वजह से नगर पालिका समय-समय पर जांच कर ऐसे मोटर पंपों को जब्त करती है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन अब सवाल तब खड़े हो रहे हैं, जब कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में नगरपालिका द्वारा ही नल कनेक्शन पर मोटर पंप लगाकर पानी की आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मोटर पंप नगर पालिका द्वारा ही लगाए गए हैं।

मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग और नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। दोनों विभागों के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्य सामने आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 58 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। फिलहाल दो केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था सामने आई है, जबकि बाकी केंद्रों की स्थिति क्या है, यह जांच का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि नगरपालिका प्रशासन इस मामले में वास्तविक जांच कर जिम्मेदारी तय करता है या फिर मामला केवल जांच की घोषणा तक ही सीमित रह जाता है।

जापान के शाही आम ने बस्तर में दी दस्तक

जगदलपुर। बस्तर अब सिर्फ धान, मक्का या पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल जापान का मियाज़ाकी आम अब बस्तर की धरती पर फलने लगा है। लाखों रुपये किलो तक बिकने वाला यह आम अगर बड़े स्तर पर सफल हुआ तो बस्तर के किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए हमारी व्यवस्था तैयार है?

पेड़ों पर लटकते ये लाल रंग के आम किसी सामान्य बाग के नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित और महंगे मियाज़ाकी आम के हैं। जापान के मियाज़ाकी प्रीफेक्चर में विकसित इस आम को 'एग ऑफ द सन' यानी सूरज का अंडा भी कहा जाता है। इसकी खासियत इसकी मिठास, रंग और सीमित उत्पादन है। कई अंतरराष्ट्रीय नीलामियों में इसकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच चुकी है। बस्तर में एक किसान ने करीब चार साल पहले इस आम का पौधा लगाया था। पूरी तरह जैविक तरीके से इसकी देखभाल की गई। गोबर खाद, नियमित गुड़ाई और बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के यह पौधा आज फलों से लद चुका है। इससे यह संकेत मिला है कि बस्तर की जलवायु इस विदेशी और प्रीमियम किस्म के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मियाज़ाकी जैसे हाई-वैल्यू फलों की खेती को प्रोत्साहन मिले, तो बस्तर में कृषि का नया मॉडल विकसित हो सकता है। जहां एक एकड़ से मिलने वाली आय पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है।

महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

जिला परियोजना अधिकारी मनोज सिन्हा ने बताया कि जिले में अबतक 75 फीसदी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करा लिया गया है.

2 हजार लोगों का योजना से कटा नाम

बस्तर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को हर महीने 1 हजार दिए जाते हैं। इस योजना के दम पर ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। अब इस योजना को लेकर बड़ी खबर ये है कि बस्तर जिले में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिला परियोजना अधिकारी मनोज सिन्हा ने बताया कि जिले में अबतक 75 फीसदी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करा लिया गया है।

जिला परियोजना अधिकारी के मुताबिक ज़िले में अब भी 25 प्रतिशत हितग्राही ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं।

इसकी वजह सर्वर में आ रही दिक्कत और फिंगर प्रिंट मिसमैच जैसी समस्याएं हैं। जिसके चलते हितग्राहियों को ई-केवाईसी करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा संबंधित जरूरी दस्तावेजों में नाम में हुई गड़बड़ी के कारण भी कई हितग्राही महतारी वंदन की योजना से दूर होते नजर आ रहे। यहीं कारण है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 हजार महिलाओं का नाम लाभार्थियों की सूची से काट दिया है।

वहीं, अब विभाग जिले में महतारी वंदन योजना की सूची को अपडेट करने की कवायद में लगा हुआ है। विभाग ने संबंधित हितग्राहियों को 30 जून तक का समय ई केवाईसी के लिए दिया है। इसके चलते चॉइस सेंटर में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की लंबी कतार नजर आ रही है। फिलहाल 2 हजार महिलाओ का जो नाम कटा है यदि उनका ई केवाईसी नहीं होता है तो उसे होल्ड में रख दिया जाएगा।

बस्तर जिले में महतारी वंदन योजना के 1 लाख 90 हजार हितग्राही है। एक महीने के अंदर जिले में 47 हजार हितग्राहियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वरना इन हितग्राहियों का नाम भी सूची से काटा जा सकता है।

हथियारबंद नकाबपोशों का लिमतरी के जैन फार्म हाउस पर धावा

बदमाश ले उड़े डेढ़ लाख नकद और सोना-चांदी

बिलासपुर। बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिमतरी स्थित जैन ऑर्गेनिक फार्म हाउस में देर रात हुई बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना के अनुसार नकाबपोश बदमाश घातक हथियारों से लैस होकर फार्म हाउस में घुसे और लाखों रुपये की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी संगीता जैन ने चकरभाठा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि उनका जैन ऑर्गेनिक फार्म हाउस ग्राम लिमतरी में स्थित है। पति प्रमोद जैन के निधन के बाद वह शहर स्थित अपने निवास में रहती हैं और दिन में फार्म हाउस की देखरेख के लिए आती-जाती हैं। फार्म हाउस के अंदर बने मकान में परिवार का सामान रखा हुआ था।

बताया गया कि 1 जून की रात करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने फार्म हाउस में प्रवेश किया। आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बाद अलमारी को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसमें रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए सामान में सोने की अंगूठी, लगभग दो तोला वजनी सोने की मूर्ति, चांदी की लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा, चांदी का लोटा,चांदी के सिक्के तथा करीब डेढ़ लाख रुपये नकद शामिल हैं। बदमाशों ने चोरी के बाद घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया ताकि पहचान न हो सके।

हालांकि वारदात की कुछ गतिविधियां कैमरों में कैद होने की जानकारी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है।

बीएमओ पर मरीज से अभद्र व्यवहार का आरोप

समाज ने की हटाने की मांग, तो बचाव में उतरे स्वास्थ्य कर्मी, काम बंद की करने की दी चेतावनी

गरियाबंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग के खण्ड चिकित्सा अधिकारी (ब्रस्ह) डॉ। प्रकाश साहू पर मरीज से अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। सुपेबेड़ा निवासी टंकधर आडील का आरोप है कि बीएमओ ने दवा मांगने पर अभद्र व्यवहार और थप्पड़ मारने की धमकी दी। जिसके बाद एक ओर समाज ने बीएमओ को हटाने की मांग तक कर दी है।

वहीं अब देवभोग ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मचारी बीएमओ के बचाव में उतर गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसडीएम को दिए पत्र में बताया गया कि बीएमओ डॉ। प्रकाश साहू अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन निष्ठा, समर्पण और सकारात्मक भाव से कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मरीजों के हित, कर्मचारियों के मार्गदर्शन और शासन की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम किया है।स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि बिना पर्याप्त तथ्यों के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे आधारहीन आरोपों से अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।कर्मचारियों ने टंकधर आडिल की शिकायत की निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच कराने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ठीहाईपारा में पानी की किल्लत ग्रामीण हो रहे परेशान

कोरिया। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत नगर अंतर्गत ठीहाईपारा में सरकार द्वारा हर घर तक स्वच्छ पेयजल दावों की जमीनी हकीकत कोसों दूर है। यहां के ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और पानी की एक-एक बूंद के लिए भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार पूरे मोहल्ले की जलापूर्ति एकमात्र पानी की टंकी और बिजली आपूर्ति पर निर्भर है। बिजली रही तो नलों में पानी आ जाता है, लेकिन जैसे ही बिजली गुल होती है, जलापूर्ति भी ठप हो जाती है। ऐसे में लोगों को पीने, नहाने और घरेलू उपयोग के लिए दूसरे मोहल्लों या दूरस्थ स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय निवासी सुशीला ने बताया कि कई बार उन्हें जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के नीचे स्थित जल स्रोतों से पानी लाना पड़ता है।उन्होंने कहा कि पानी की कमी के कारण रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक उनमें नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी।

नारायण मंदिर परिसर में हरिहर महायज्ञ का आयोजन 5 से

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय के निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रवीर वार्ड पनारा पारा स्थित श्रीभूवेश्वर महादेव मंदिर एवं श्रीलक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में हरिहर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास (अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष) के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन में नौ दिनों तक वैदिक अनुष्ठान, पूजन, अर्चन, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में सनातनी वेशभूषा में शामिल होकर धर्म और संस्कृति के इस महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है। महायज्ञ की शुरुआत 5 जून को पंचमी तिथि पर शाम 6 बजे अंकुरारोपण के साथ होगी। वैदिक परंपरा के अनुसार यह अनुष्ठान किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की मंगल शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 8 जून को प्रातः 6 बजे काया शुद्धि का आयोजन होगा, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि और धार्मिक संकल्प के साथ यज्ञीय कार्यक्रमों को गति दी जाएगी।

लखपति दीदी रत्ना बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

जगदलपुर। लखपति दीदी रत्ना ठाकुर ने मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आज वह न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि क्षेत्र की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। रत्ना ठाकुर ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर के माध्यम से मुर्गीपालन के लिए दाना तैयार कर रही हैं। उनके द्वारा निर्मित दाने की मांग स्थानीय कुक्कुटपालकों के अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों तक है। इससे उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है। रत्ना ने बताया कि दाना निर्माण के साथ-साथ वह ब्रूडिंग चूजों का पालन-पोषण कर उन्हें बड़ा करती हैं और बाद में होटल एवं ढाबों में उनकी आपूर्ति करती हैं। इस व्यवसाय ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रत्ना ने कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। करीब दो एकड़ भूमि पर मल्चिंग विधि से साग-सब्जियों की खेती कर वह हर माह 15 से 20 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं।

महासर वाली माता के मंगल पाठ एवं भजनों पर झूमे श्रद्धालु

राजनांदगांव। संस्कारों की जननी संस्कारधानी राजनांदगांव में श्री सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा आयोजित 16 दिवसीय पुरुषोत्तम मास श्री नारायण महामहोत्सव में प्रतिदिन भक्ति, श्रद्धा और संस्कारों की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। श्री नारायण धाम स्थित श्री सत्यनारायण धर्मशाला, कामठी लाइन में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म लाभ प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। श्री सत्यनारायण मंदिर समिति के उत्सव प्रभारी श्याम खंडेलवाल, राजेश अग्रवाल एवं विजय खंडेलवाल ने बताया कि महामहोत्सव के द्वितीय दिवस महासर वाली माता महिला मंडल द्वारा महासर वाली माता का मंगल पाठ श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भजन गायक अभिजीत जोशी ने अपनी मधुर एवं ऊर्जावान भजन प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों की स्वर लहरियों पर श्रद्धालु देर तक झूमते, नाचते और प्रभु भक्ति में लीन होकर आनंदित होते रहे। पूरा पंडाल जयकारों और भक्ति रस से गुंजायमान रहा।

परेशान किसानः खेत में बंद ट्रैक्टर को खींचकर लाए दफ्तर

बस्तर। छत्तीसगढ़ में अब डीजल पेट्रोल की किल्लत का असर खेती किसानी में भी दिखने लगा है। बस्तर क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों को डिब्बे में डीजल लेने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ रही है। बिना एसडीएम के परमिशन के पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल डिब्बों में नहीं मिल रहा है। ऐसे में तेल की कमी से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। तेल की कमी के कारण खेतों में काम कर रहे कई ट्रैक्टर डीजल खत्म होने के बाद खेत में ही बंद हो गए। मजबूरी में किसानों को ट्रैक्टर खींचकर कार्यालय तक पहुंचना पड़ा, ताकि अनुमति पत्र लेकर डीजल लिया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों की नाराजगी का ही असर है कि ट्रैक्टर को स्ष्ठरूकार्यालय लाकर आक्रोशित नजर आए और जमकर नारेबाजी की गई। इन्द्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि खेती के सीजन की तैयारियों के बीच डीजल की उपलब्धता बाधित होने से खेती के कार्य ठप पड़ रहे हैं।

तमिलनाडू में बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया

जांजगीर चांपा के मजदूरों को तमिलनाडू में बंधक बनाया गया था,जिन्हें जिला प्रशासन की मदद से मुक्त कराया गया हैं

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में एक ओर सुशासन तिहार मना कर राज्य की खुशहाली का दावा किया जा रहा है, वहीं जांजगीर चांपा जिला में अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है।

श्रम विभाग के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों को मुक्त कराया गया।

जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे 9 बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए हैं।मामले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों के विषय में जानकारी लेते हुए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन ने कलेक्टर ने चर्चा की और मजदूरों को रिहा कराया। जिला प्रशासन की पहल पर बंधक बने मजदूरो को मुक्त करा लिया गया है। जिन्हें ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कराया गया है।

तमिलनाडू के तिरुवल्लुर जिला मे देवाद्वकाम गांव में बंधक बनाए गए मजदूरों से कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने फोन पर चर्चा की। मजदूरों ने बताया कि उन्हें घरेलू काम कराने के लिए लाया गया था, कुछ दिन के बाद मजदूरों से 12-14 घंटा काम कराया जाने लगा। काम के बदले उन्हें पर्याप्त मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था।इसके बाद बंधक बने मजदूरों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। मजदूरों की फरियाद सुनने के बाद कलेक्टर ने मजदूरों की रिहाई के लिए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन से चर्चा की और श्रमिकों को अवमुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर ट्रेन से छत्तीसगढ़ रवाना किया।

डीईओ की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

कलेक्टर के नाम से जारी किया आदेश, आरटीआई मामलों में भी लापरवाही का आरोप

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मनीराम यादव एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। डीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि विभागीय नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के आधिकारिक लेटरपैड का उपयोग करने के बजाय कई मामलों में कलेक्टर कार्यालय के नाम से आदेश जारी कर रहे हैं। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने में असफल रहे हैं। कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को दरकिनार कर बाहरी लोगों से काम लिया जा रहा है। इस बीच डीईओ पर यह भी आरोप है कि विद्यालयों से मंगाए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कार्यालय में रखने के बजाय निजी निवास पर ले जाया जाता है। सूत्रों का कहना है कि कई बार संबंधित शाखा के कर्मचारियों को भी इन दस्तावेजों की जानकारी नहीं होती, जिससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित होते हैं।सूचना के अधिकार (आरटीआई) के मामलों में भी गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों आरटीआई आवेदन लंबित पड़े हैं, जबकि आवक-जावक शाखा को भी कई मामलों की जानकारी नहीं दी जाती। इससे आवेदकों को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही है।

गौरतलब है कि जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव पूर्व में भी कई विवादों और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले में जिले के नवनियुक्त कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी से टेलिफोनिक चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है अगर ऐसा आदेश जारी किया जा रहा है तो विधिवत जांच कराई जाएगी और उचित क्रिया भी लिया जाएगा।

साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतर्क

प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण, नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को समय पर खाद एवं कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मार्कफेड तथा जिला प्रशासन के समन्वय से पूरे प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

राज्य सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावनाओं को देखते हुए अग्रिम तैयारी की है। उर्वरकों के पर्याप्त भंडारण, समयबद्ध परिवहन और किसानों तक सुगम वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों, कृषि अधिकारियों, सहकारिता विभाग तथा मार्कफेड को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर रोक लगाने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 9.29 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का स्टॉक गोदामों और सोसायटियों में उपलब्ध है। जबकि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को इस खरीफ सीजन के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आबंटित हुआ हजिसमें यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख तथा एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश के गोदामों एवं समितियों में लगभग 9.29 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है।

कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव ने बताया कि किसानों को पर्याप्त खाद्य मिले

इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जून 2026 अंतर्गत 1 जून 2026 की स्थिति में रेक प्वाइंट तिल्दा, जिला रायपुर में 1319 मीट्रिक टन यूरिया, रेक प्वाइंट बेलसोंडा महासमुंद 1316 मीट्रिक टन यूरिया इसी प्रकार रेक प्वाइंट खरसिया, जिला रायगढ़ 2646 मीट्रिक टन यूरिया और रेक प्वाइंट जिला बालोद में 1319 मीट्रिक टन यूरिया, इस तरह कुल 6600 मीट्रिक टन यूरिया की खेप आने वाली हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद जिले में वर्तमान में 17,818 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक तथा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसी प्रकार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की मुकुरमुडा समिति में खरीफ सीजन के लिए 362 मीट्रिक टन उर्वरकों का अग्रिम भंडारण किया गया है। किसानों को गांवों के निकट ही खाद उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त गोदामों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मुंगेली जिले में यूरिया वितरण के दौरान तकनीकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुई अस्थायी स्थिति का तत्काल समाधान कर प्रशासन एवं कृषि विभाग की निगरानी में किसानों को व्यवस्थित रूप से खाद उपलब्ध कराया गया। बस्तर जिले में खरीफ 2026 हेतु उर्वरक भंडारण एवं वितरण का कुल लक्ष्य 46,050 मीट्रिक टन निर्धारित है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास 18,341 मीट्रिक टन तथा मार्कफेड एवं थोक विक्रेताओं के पास 11,378 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में कुल 29,719 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 64 प्रतिशत है।

रायपुर जिले में यूरिया की समितियों में वर्तमान उपलब्धता 9,102 मीट्रिक टन है, जबकि संग्रहण केंद्रों से कुल 10,732 मीट्रिक टन यूरिया भंडारित किया गया है। इसी प्रकार डी.ए.पी. की समितियों में वर्तमान उपलब्धता 3,092 मीट्रिक टन है, जबकि कुल भंडारित मात्रा 3,927 मीट्रिक टन है। किसानों की सुविधा और सुचारू वितरण व्यवस्था के लिए भूमि की उपलब्धता के आधार पर यूरिया के वितरण की किश्तें भी निर्धारित की गई हैं। इसके तहत ढाई एकड़ तक की भूमि वाले सीमांत कृषकों को निर्धारित यूरिया की मात्रा एकमुश्त प्रदाय की जाएगी। ढाई एकड़ से पांच एकड़ तक की भूमि वाले लघु कृषकों को उर्वरक का उठाव दो किश्तों में करने की सुविधा होगी, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े कृषकों को यूरिया का प्रदाय तीन किश्तों में सुगमतापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर में सफाई ठेकेदारों की हड़ताल शुरू 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने का आरोप

रायपुर। शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट

गहरा गया है। चेतावनी के बाद बुधवार सुबह से सफाई ठेकेदारों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। कई महीनों से अटके भुगतान बहाल करने की मांग की जा रही है। अब निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में सफाई कार्य ठप हो गया है। ठेकेदारों का कहना है कि एक महा में सभी वार्डों को मिलाकर 4 करोड़ का भुगतान होता है लेकिन पिछले चार माह से भुगतान नहीं हुआ है। हमे भी सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ता है। कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। अब भुगतान नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताल पर गए ठेकेदारों ने बताया कि पिछले सप्ताह नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि जारी करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ठेकेदारों ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को भी ज्ञापन सौंपा था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामकी कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर दिया था। ऐसे में अब ठेकेदारों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।

06 जून से 09 जून तक होगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 06 जून से 09 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संपन्न होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 06 जून 2026 को भाषा एवं निबंध, 07 जून को सामान्य अध्ययन-I एवं II, 08 जून को सामान्य अध्ययन-III एवं IV तथा 09 जून को सामान्य अध्ययन-V की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र दिनांक 25 मई 2026 को अभ्यर्थियों को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या स्व्रू व्यक्तिश: नहीं भेजा जाएगा।

दिल्ली रेस्टोरेंट अग्नि दुर्घटना में जनहानि पर मुख्यमंत्री ने किया शोक व्यक्त

रायपुर। बुधवार की सुबह दिल्ली के मालवीय

नगर स्थित होटल में आग की दुर्घटना में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि यह समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। इस हादसे में अपनों को खोने वाले सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, शोकसंतप्त परिवारों को इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करें तथा सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।

कृष्णपुर जलाशय योजना के नवीनीकरण के लिए 2.73 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग ने सूरजपुर जिले के विकासखण्ड रामानुजनगर की कृष्णपुर जलाशय योजना के नवीनीकरण कार्य के लिए 2 करोड़ 73 लाख 29 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के किसानों को कुल 151 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे खरीफ और रबी फसलों का रकबा बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। जल संसाधन विभाग ने योजना के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। विभाग ने कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कृष्णपुर जलाशय के नवीनीकरण कार्य से क्षेत्र में जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भू-जल स्तर में भी सुधार होगा।

सिंधी अकादमी अध्यक्ष सुषमा मिली भाजपा प्रवक्ता चिमनानी से

रायपुर। सिंधी अकादमी की नवनियुक्त

अध्यक्ष सुषमा जेठानी ने भाजपा प्रवक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित चिमनानी से मुलाकात कर आभार जताया। इस दौरान सिंधी अकादमी के संचालन के विभिन्न विषयों एवं आगामी कार्यक्रमों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। अमित चिमनानी ने श्रीमति सुषमा जेठानी को उनके सफलतम कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की।

अवैध रेत उत्खनन पर राज्यपाल सख्त, बोले-

नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ मंजूर नहीं : डेका

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध व बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस पर तत्काल व प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, परंतु इसके अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा की और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे।

राज्यपाल ने अवैध उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि अंधाधुंध खुदाई के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी के तल में अत्यधिक गहराई तक खुदाई होने से उनकी जलधारण क्षमता घट रही है, जिसका सीधा प्रतिकूल असर भू-जल स्तर पर पड़ रहा है। नदी तटों के तीव्र कटाव की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जलस्रोत सूख रहे हैं और जलीय जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों व बड़े नालों की जल क्षमता को बनाए रखने तथा भू-जल स्तर में सुधार के लिए अब दीर्घकालिक और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

भविष्य की कार्ययोजना पर बात करते हुए राज्यपाल डेका ने निर्देश दिए कि रेत खनन से प्रभावित क्षेत्रों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खनन के सटीक आकलन, तकनीकी अध्ययन और सर्वे के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए रेत बेहद जरूरी है, लेकिन इसका दोहन निर्धारित नियमों और वैज्ञानिक मानकों के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देशित किया कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए संपूर्ण खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

13 को एनएचएम कर्मचारियों का महासम्मेलन मुख्यमंत्री साय होंगे मुख्य अतिथि

प्रदेशभर से 18 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 13 जून 2026 को रायपुर स्थित स्व. बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया है। यह महासम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एकजुटता, समर्पण और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित होगा।

महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश के उप-स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों,

जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, मंत्रालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 18 हजार से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने परिवार सहित सहभागी होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने प्रदेशभर के जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

महासम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 21 वर्षों की स्वास्थ्य सेवा यात्रा, कर्मचारियों के योगदान, संघर्ष एवं उपलब्धियों का सामूहिक उत्सव होगा। यह आयोजन कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय, संवाद और संगठनात्मक एकता को नई दिशा प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट कर महासम्मेलन में शामिल होने आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की, जिससे प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारियों में विशेष उत्साह का वातावरण है। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, डॉ. रविशंकर दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास, डॉ. आलोक शर्मा एवं डॉ. तृप्ति तिवारी उपस्थित रहे।

सीजीपीएससी भर्ती घोटाला

सोनवानी, ध्रुव, आरती व ललित के यहां ईडी की दबिश

रायपुर-धमतरी-भिलाई-राजनांदगांव। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला प्रकरण में ईडी की टीम बुधवार को पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, जेके ध्रुव और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक व सहायक नियंत्रक ललित गनवीर के ठिकानों पर दबिश दी।

समाचार लिखे जाने तक ईडी की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी की टीम भिलाई के सेक्टर-10 स्थित रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के निवास तथा रायपुर स्थित आरती वासनिक के घर पहुंची। इसके साथ ही ईडी की टीम बुधवार को पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के धमतरी के पास गृह ग्राम सरबदा पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा राजनांदगांव के स्टेशन पारा स्थित ललित गनवीर के घर पर छापेमारी की। रायपुर में कटोरा तालाब स्थित आरती वासनिक और भिलाई में जेके धुव्र के निवास पर ईडी की कार्रवाई के दौरान परिसर के बाहर सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे। सोनवानी, ध्रुव और वासनिक वर्तमान में जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में हेरफेर कर कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा प्रश्नपत्र लीक किए गए।

आजादी के 78 साल बाद रोशन होंगे दूरस्थ मजराटोले

रायपुर। सुशासन तिहार-2026 के अवसर पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले के 10 दूरस्थ एवं अब तक विद्युत सुविधा से वंचित मजराटोलों के विद्युतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों में इसी सत्र के दौरान तेजी से विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किया जाएगा।

आजादी के 78 वर्षों बाद जिले के ऐसे दूरस्थ वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां अब तक अंधेरा ही ग्रामीणों की नियति बना हुआ था। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत निजामडीह, तुम्दादाह, बलरामपुर, कोहकझोरी, संजारी-टाटीघाट, झिलमिली एवं गाताभर्री, घाघरा, लमरा, रिहाडबरा तथा टिनगीपुर जैसे गांवों के मजराटोलों में विद्युत नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

विद्युतीकरण से न केवल घरों में रोशनी पहुंचेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और आजीविका के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बिजली उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सुविधाएं, छोटे व्यवसाय और शासकीय सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। लंबे समय से बिजली की मांग कर रहे ग्रामीणों के लिए यह निर्णय किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है।

एक्सप्रेस-वे से गुढ़ियारी आने-जाने के लिए आज से 14 दिनों तक बदलना पड़ेगा रूट

- **ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी**

रायपुर। रायपुर स्टेशन यार्ड के बिलासपुर एंड पर स्थित एक्सप्रेस-वे से गुढियारी आने-जाने वाले लोगों को अगले 14 दिनों तक रूट बदलना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मेंटेनेंस कार्य के चलते गुढ़ियारी रेलवे अंडर ब्रिज को 4 जून से 18 जून तक इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक रेलवे स्टेशन की ओर से एक्सप्रेस-वे होते हुए गुढ़ियारी जाने वाले वाहन इस दौरान अंडरब्रिज से नहीं गुजर सकेंगे। रोजाना इस मार्ग का उपयोग करने वाले हजारों लोगों को वैकल्पिक रास्तों से सफर करना होगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज-380 में मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाने के चलते 4 जून से 18 जून 2026 तक इस मार्ग पर सड़क यातायात बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को तेलघानी नाका ओवरब्रिज और चुनाभट्टी अंडर ब्रिज का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों से अतिरिक्त समय लेकर निकलने और डायवर्जन प्लान का पालन करने की अपील की है।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक रायपुर-गुढियारी (बिलासपुर एंड) स्थित रेलवे समपार 380 में आवश्यक कवर शेड और पाइप डालने का काम किया जाएगा। इसके चलते रेलवे स्टेशन की ओर से गुढियारी जाने वाले अंडरब्रिज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकने का फैसला लिया गया है।

रेलवे और ट्रैफिक विभाग का कहना है कि काम पूरा होने के बाद मार्ग को फिर से सामान्य आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश का पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला

नॉर्थ गोवा में होटल वेस्टिन, शराब घोटाले की अवैध कमाई से खरीदी गई थी : भाजपा

- **बघेल और कांग्रेस के मौन को क्या उनकी स्वीकृति मान लिया जाए?**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए छठवें आरोप पत्र के बाद इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है। श्री ठोकने ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल छोटी-छोटी बातों पर मीडिया के सामने माइक लपकने में देरी नहीं करते, वे आज इतने गम्भीर मामले पर

मुँह में दही जमाए बैठे हैं! इससे साफ है कि बघेल के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है।

ठोकने ने बुधवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के सामने वेस्टिन होटल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि नॉर्थ गोवा में स्थित इस आलीशान होटल को छत्तीसगढ़ के अवैध शराब घोटाले की कमाई से खरीदा गया था। ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए श्री ठोकने ने कहा कि इस होटल को खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ से करीब 110 करोड़ रुपए की अवैध नगदी गोवा भेजी गई थी। ईडी के छठवें आरोप पत्र के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के इशारे पर ही यह भारी-भरकम राशि गोवा शिफ्ट की गई थी। श्री ठोकने ने कांग्रेस की चुप्पी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, पहले भी भाजपा ने यह प्रश्न उठाया था और आज भी पूछ रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर मौन है। क्या उनके इस मौन को उनकी स्वीकृति मान लिया जाए? श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में पूर्ण शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपनी पार्टी का एटीएम बना दिया। ईडी की जाँच की प्रगति से अब यह बात पूरी तरह सच साबित हो रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, गरियाबंद छत्तीसगढ़

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 01/व.ले.लि./ का.अ./ लो.स्वा. यां. / खण्ड 2026 गरियाबंद, दिनॉक 29-05-2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रू.लाख में)	अमानत राशि
1.	गरियाबंद जिले के विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम पोखरा के अंतर्गत कोपरा-पोखरा मुख्य जिला मार्ग चौडीकरण उन्नयन कार्य में 90mm dia UPVC 6kg/cm^2 लंबाई 1350 मीटर प्रदाय कर जोड़ने, बिछाने, इन्टरकनेक्शन, परीक्षण कर चालू करने तथा अन्य सिविल कार्य। शेड्यूल अनुसार	6.48 लाख	4860/-

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में दिनांक 15-06-2026 तक देखी जा सकती हैं।

जी-262701116/2

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी खण्ड,
गरियाबंद (छ.ग.)

आखिर खंड-खंड क्यों हो रही टीएमसी?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन चुनाव आयोग से उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में एक राजनीतिक दल थी या फिर एक निजी कंपनी की तरह संचालित होने वाला संगठन? आलोचकों का आरोप रहा है कि इसकी चेयरपर्सन ममता बनर्जी थीं, मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी, जबकि निर्णय प्रक्रिया पर एक सीमित समूह का प्रभाव था। तृणमूल कांग्रेस 15 वर्षों तक सत्ता में रही। यही सत्ता उसके संगठनात्मक अंतर्विरोधों को ढकने का सबसे बड़ा कारण थी। सत्ता का आकर्षण और सत्ता का भय दोनों ने नेताओं को पार्टी में बनाए रखा। जो नेता पार्टी छोड़कर गए, उनके साथ प्रशासन और पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, यह किसी से छिपा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर अर्जुन सिंह तक अनेक नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया और विभिन्न मामलों में उलझाया गया। ममता बनर्जी के पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों को लेकर यह शिकायत लंबे समय से रही कि अभिषेक बनर्जी के दौर में उनकी भूमिका सीमित होती चली गई। स्वयं ममता बनर्जी भी सार्वजनिक रूप से यह कह चुकी हैं कि कई लोग उनसे अभिषेक को राजनीति से दूर रखने की सलाह देते थे। दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी की अपनी एक टीम थी, जो संगठन और सत्ता दोनों में प्रभावशाली मानी जाती थी। लेकिन आज वही टीम लगभग अदृश्य दिखाई दे रही है। डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के दौरान और उसके बाद भी उनके कई करीबी नेता सक्रिय नहीं दिखे। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जा सकता है कि इन नेताओं ने अपना राजनीतिक भविष्य अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से जोड़ रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि ममता बनर्जी के बाद वही पार्टी और सरकार का नेतृत्व करेंगे। सत्ता परिवर्तन के साथ यह संभावना भी कमजोर पड़ गई। यदि इस टूट और बिखराव के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाए, तो आरोपों का केंद्र अभिषेक बनर्जी बनते हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता सहज नहीं थे। ममता बनर्जी का प्रभाव और प्रशासनिक कार्रवाई का भय असंतोष को दबाए हुए था। सत्ता से बेदखली के साथ ही यह भय समाप्त हो गया और वर्षों से जमा असंतोष बाहर आने लगा। सत्ता गंवाने के 48 घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई। बताया जाता है कि 80 विधायकों में से केवल 19 विधायक ही पहुंचे। 2 जून के धरना-प्रदर्शन में भी 120 जनप्रतिनिधियों में से मात्र 14 की उपस्थिति दर्ज हुई। 29 लोकसभा सांसदों में केवल 2 और 13 राज्यसभा सांसदों में केवल 4 सांसद मौजूद थे। यह उपस्थिति स्वयं संगठन की मौजूदा स्थिति का संकेत देती है। यह घटनाक्रम पहली नजर में महाराष्ट्र की राजनीति जैसा दिखाई देता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में मूलभूत अंतर है। महाराष्ट्र में दल-बदल का उद्देश्य सत्ता में भागीदारी हासिल करना था, जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में टूटकर अलग होने वाले नेताओं के सामने तत्काल सत्ता प्राप्ति का अवसर नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति की भूमिका है। ममता और अभिषेक बनर्जी की नजर में इस घटनाक्रम के प्रमुख सूत्रधार ऋाोब्रत्तो बंदोपाध्याय हो सकते हैं, लेकिन असली प्रश्न इससे कहीं बड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में विधायक और नेता क्यों अलग हुए? अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक भी इस प्रक्रिया में क्यों शामिल हुए? अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेता भी क्यों दूर हो गए? इन सवालों का सबसे बड़ा उत्तर शायद यही है कि पार्टी के भीतर संवाद और असहमति की गुंजाइश लगातार कम होती गई।

योगी ने आतातायियों को दिया सख्त संदेश

मनोज कुमार अग्रवाल

आखिर यूपी पुलिस ने बकरीद के दिन एक सत्रह साल के हिन्दू छात्र की चाकू घोंप कर नृशंसता भरी बर्बर हत्या करने वाले मुख्य हत्यारे असद का एनकाउंटर कर अराजक हिंसक तत्वों को कड़ा संदेश दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कड़े निर्देश दिए उन्होंने शोहदों और ऐसे अपराध करने वाले युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि नालायक औलादों को समझाना जरूरी है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार कानून का पालन करने वाले आम नागरिकों के साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा संदेश साफ है कि यूपी को बांग्लादेश या पाकिस्तान समझना भूल होगी। बर्बरता और जघन्यता का माकूल जबाव पुलिस बिना देरी के देगी।

आपको बता दें देश के कई इलाकों में जिस तरह की सांप्रदायिक नफरत और प्रतिशोध से भरी वारदातें सामने आती हैं उस से लगता है कि इन वारदातों के पीछे कोई ऐसी पूरी सुनियोजित साजिश रहती है जो नफरत और खूनी दरिंदगी भरी मानसिकता का बीजारोपण करती है पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इस से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में ऐसी कई बर्बरता भरी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है जिनसे लगता है कि कानूनी सख्ती के बावजूद दरिंदों में पुलिस और कानून का रंचमात्र भय नहीं है। ताज़ा घटनाक्रम में गाजियाबाद से एक बेहद सनसनीखेज और कलेजा कँपा देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन एक 17 वर्षीय हिंदू किशोर, सूर्या चौहान की उसके ही पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले कट्टरपंथी हमलावरों ने पीड़ित से पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज तुझे दिखाते हैं।

आरोप है कि यह कहते ही उन्होंने सूर्या पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने रविवार के तड़के मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है इस से पहले 3 नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया ।

आपको बता दें मृतक सूर्या चौहान मूल रूप से एटा का रहने वाला था। वह नवनीत विहार, खोड़ा में अपनी माँ, बड़े भाई यश चौहान और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता कौशलेंद्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सूर्या 11वीं कक्षा का छात्र था। जानकारी के मुताबिक, करीब 8 महीने पहले सूर्या का पड़ोस में रहने वाले असद नाम के युवक से किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था।

इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए असद ने बकरीद के पवित्र दिन को चुना। 28 मई की दोपहर को असद ने सूर्या को फोन किया। उसने सूर्या को बकरीद की पार्टी के बहाने मिलने के लिए चौधरी स्कूल के पास वाली गली नंबर 2 में बुलाया। सूर्या अपने दोस्त आयुष और विक्की के साथ असद से मिलने पहुँचा था। विक्की और आयुष ने आँखों देखा हाल बताते हुए बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। विक्की ने बताया कि जैसे ही वे गली में पहुँचे, वहाँ पहले से ही असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत 5 से 6 मुस्लिम युवक हथियारों के साथ घात लगाकर बैठे थे बताया जा रहा है कि आते ही उन्होंने सूर्या को चारों तरफ से दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक और हिंसक टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? बताया गया है कि आरोपितों ने चिल्लाते हुए कहा कि आज बकरीद है और आज कुर्बानी इस हिंदू लड़के की देंगे। यह कहते ही सभी आरोपितों ने सूर्या पर बड़े चाकुओं से हमला बोल दिया। उन्होंने सूर्या के पेट, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ कई वार किए। हमला इतना बर्बर था कि चाकुओं की गोदने की वजह से सूर्या की आंतें तक बाहर आ गईं।मौके पर चीख-पुकार और शोर मच गया। शोर सुनकर पास ही मौजूद सूर्या का भाई यश चौहान और उसकी माँ दौड़ते हुए घटना स्थल की तरफ भागे। परिजनों को अपनी तरफ आता देख सभी मुस्लिम हमलावर खून से लथपथ सूर्या को तड़पता हुआ छोड़कर मौके से फरार हो गएपरिजन आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल सूर्या को नोएडा के सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अगले दिन यानी 29 मई को दोपहर करीब 12 बजे सूर्या ने दम तोड़ दिया। सूर्या की मौत की खबर जैसे ही खोड़ा इलाके में फैली, वहाँ भारी रोष और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई।

हिंदू समाज का कहना है कि यह केवल दो गुटों की लड़ाई नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद और इस से सटे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में हत्या के कुछ हालिया मामलों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े आरोपियों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, पुलिस जांच और आधिकारिक रिपोर्टों में इन घटनाओं को सुनियोजित या समुदाय-विशिष्ट घृणा के बजाय मुख्य रूप से आकस्मिक विवादों, पुरानी दुश्मनी या आपसी रंजिश का परिणाम बताया गया है।आपको दो माह पहले जेजे कालोनी उत्तम नगर की नृशंसता भरी वारदात याद होगी यहां हिन्दू त्योहार होली के दिन रंग-बिरंगे पानी के छींटे पड़ने और गुब्बारा लगने को लेकर दो समुदाय से जुड़े परिवारों के बीच विवाद हुआ था। इस घटना में 26 वर्षीय तरुण कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी दिन यानि होली के दिन ही सिगरेट के विवाद में सूरज नामक 26 वर्षीय हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में सादिक नामक आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। और अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक 16 वर्षीय छात्र सूर्या की उसके ही परिचित अशद द्वारा चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है।

यकीनन ये वारदातें अराजक व कम्युनल अपराधियों के बढ़ते हौसले का सबूत है। एक न्यूज रिपोर्ट में मृतक की मौसी सुनीता ने कहा, मैं सबसे पहले अस्पताल गई थी। मैंने उन्हें वहां देखा। वे यह साबित करना चाहते थे कि पहले बकरे की कुर्बानी दी और अब वे इंसान की कुर्बानी देंगे। बकरीद के दिन मेरे बच्चे को धोखे से घर से बुलाया गया। फिर उससे पूछा गया कि बकरा कैसे काटा जाता है। हिंदू बच्चों को ऐसी बातों के बारे में क्या पता? हमारे बच्चों ने कभी खून-खराबा नहीं देखा। वे क्या कहते? यही कहते कि उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई।

सवाल यह है कि इस तरह की दरिंदगी और बर्बरता की सोच को कौन उकसा रहा है? बकरीद से दो दिन पहले ही गाजियाबाद से सटे हापुड़ जनपद के पिलखुवा में एक शनिदेव प्रतिमा को एक समुदाय विशेष के एक जेहादी ने तोड़ दिया बाद में सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिले सबूत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी मनमानी घृणा और विद्वेष की बातें बहुलता से वायरल हो रहीं हैं यह एक स्वस्थ समाज की संरचना को तोड़ रहा है और परस्पर जहरीली सोच तैयार कर रहा है सरकार को गंभीरता से सख्त कदम उठाने चाहिए और इस जहर की फसल को बीजनाश करनी चाहिए यूपी की धरती पर आतंक और नफरत की फसल तैयार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा ।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इस तरह बहुत काल बीत जाने पर महातेजस्वी साठ हजार कुमार उन बर्तनों में से प्रादुर्भूत हुये, यथा-

एवं क्रमेण सञ्जातास्तनयास्ते महीपतेः।
ववृधुः संघशो राजन्षष्टिसाहस्रसंख्यया।।
(ब्रह्माण्डपुराण, उपदूधातपाद 56 ।7)

वैदिक स्वरूप

षष्टिं सहस्रा नर्वात च कौरम आरूशमेषु दद्महे।
(अथर्व 20 ।127।1)

अर्थात्- साठ हजार नब्बे मांसपेशियों को आधान पात्रों में प्रदान किया।

जान पड़ता है कि महाराजा सगर के वीर्याधान करने पर किसी खास कारणवश रानी के गर्भाशय में वीर्यगत कीटाणुपुञ्ज मक्खियों के छत्ते की भाँति पृथक् पृथक ही जरायु कोश में संश्लिष्ट रहे।

गभर्भाशय के स्वल्पावकाश के कारण और प्रत्येक कीट को उचित परिपोषक रस के न मिल सकने के कारण भी वे सब कीट परिपुष्ट होकर हाथ पांव आदि अङ्गों का विकाश न पा सके, परन्तु अमोघ वीर्य होने के कारण वे विनष्ट भी नहीं हुए। आजकल भी प्रकृति के वैलक्षण्य से कभी कभी स्त्रियों के पेट से दो चार तक बच्चे पैदा होते देखे जाते हैं तथा कभी कभी मांसपेशियों की दशों थेलियें उत्पन्न होती देखी गई हैं।

यह घटना गर्भ में वीर्यगत कीटाणुओं के एक से अधिक संख्या में बने रहने पर ही घटित हो सकती है, सो इससे महारानी के उदर में भी प्रकृति के नियन्त्रण से बहुत से कीटाणुवों का बने रहना अनुमान सिद्ध है।

जिज्ञासा हो सकती है, कि पुराणों में तो सगर पुत्रों की संख्या साठ हजार लिखी है परन्तु वेद में इसके विपरीत साठ हजार और नब्बे बताई गई है- इस विरोध का क्या कारण है?

क्रमशः ...

सुरों के बादशाह थे एसपी बालासुब्रमण्यम

अनन्या मिश्रा

संगीत की दुनिया के बादशाह रहे एसपी बालासुब्रमण्यम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज ही के दिन यानी की 04 जून को एसपी बाला का जन्म हुआ था। उनकी खनकती आवाज सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दक्षिण सिनेमा में नाम बनाने के बाद बालासुब्रमण्यम ने बॉलीवुड का रुख किया था और वह अपने पहले ही गाने से इंडस्ट्री में छा गए थे। एसपी बाला ने मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी समेत 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं।

मद्रास में एक तेलुगु परिवार में 04 जून 1946 को एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम एसपी सांबामूर्ति था, जोकि एक कलाकार थे और उन्होंने नाटकों में भी अभिनय किया था। वहीं इनकी मां का नाम शकुंतलम्मा था।

बता दें कि साल 1966 में बालासुब्रमण्यम ने तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रमन्ना के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरूआत की थी। इसके लिए उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 6 बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था। वहीं साल 2001 में उनको पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। एसपी बाला ने रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, कमल हासन, अनिल कपूर और गिरीश कर्नाड के लिए वॉइस ओवर भी किया है। वहीं डबिंग के लिए सिंगर को नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोकि थिएटर, तेलुगु सिनेमा और टीवी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है।

हिंदी से ज्यादा तमिल और तेलुगू फिल्मों के लिए बालासुब्रमण्यम ने गाने गाए हैं। लेकिन 80-90 के दशक में वह बॉलीवुड के रोमांटिक गानों के लिए जाने जाते थे। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री इतनी धमाल की थी कि पहली फिल्म एक दूजे के लिए में गाना गाने के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ पुरूष पार्श्वगायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। एसपी बाला द्वारा गाया गया गाना हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है।

सिंगर ने यह गाना स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ गाया था। इसके बाद फिल्म साजन और मैंने प्यार किया सहित सलमान खान की कई फिल्मों के गाने गाए थे। कहा जाता था कि वह सलमान खान की आवाज बन गए थे। उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए थे। वहीं 8 फरवरी 1981 को एसपी बाला ने सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटों में 21 कन्नड़ गाने रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा उन्होंने एक दिन में 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने भी रिकॉर्ड कर चुके हैं।

वहीं 05 अगस्त 2020 को बालासुब्रमण्यम को कोविड हो गया। जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। हालांकि उन्होंने कोविड के खिलाफ जंग जीत ली थी। लेकिन उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, वहीं एक महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद 25 सितंबर 2020 को एसपी बालासुब्रमण्यम ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।

म्यांमार का नई दिल्ली के साथ संबंधों को प्राथमिकता

नीरज कुमार दुबे

भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को नई रणनीतिक धार देने वाली उच्चस्तरीय वार्ता ने दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर में बड़ा संदेश दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर साफ संकेत दिया कि वह चीन की बढ़ती पकड़ से संतुलन बनाने के लिए नई दिल्ली के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट आश्वासन दिया कि म्यांमार की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह संदेश केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार में सक्रिय उन सशस्त्र गुटों के लिए भी था जो लंबे समय से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। इस वार्ता के जरिए भारत ने म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामरिक साझेदारी के मामले में नई दिल्ली अब अधिक आक्रामक और निर्णायक भूमिका निभा रही है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वार्ता के बाद बताया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई। यह क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अहम हिस्सा बन चुका है क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा परिवर्तन और अर्धचालक उद्योग में इन खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से इन संसाधनों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में म्यांमार के साथ सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। म्यांमार दुर्लभ मृदा संसाधनों से समृद्ध देश है और भारत इस क्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है।

दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत म्यांमार का विश्वसनीय पड़ोसी, भरोसेमंद सहयोगी और संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला देश बना रहेगा। यह दृष्टिकोण भारत की 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' नीति के अनुरूप है।

वार्ता में सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया कि उनकी भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच लगभग सोलह सौ चालीस किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में म्यांमार के भीतर अस्थिरता, सशस्त्र समूहों की गतिविधियां, अवैध तस्करी और सीमा पार घुसपैठ भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। विशेष रूप से मणिपुर में जातीय तनाव और हिंसा के बाद सीमा प्रबंधन का महत्व और बढ़ गया है।

भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग का केंद्र प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत विकास रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। साथ ही दोनों देशों ने संपर्क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विशेष रूप से कलादान बहु माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। यह परियोजना भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का प्रमुख आधार मानी जाती है।

देखा जाये तो इस पूरी वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन लगातार आर्थिक और सामरिक विस्तार कर रहा है। म्यांमार में भी चीन की बड़ी निवेश परियोजनाएं और बंदरगाह विकास योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में भारत म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत कर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत के लिए म्यांमार केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला सामरिक द्वार है। इसलिए नई दिल्ली इस संबंध को आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा तीनों स्तरों पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में शांति, स्थिरता और समावेशी संवाद के समर्थन की भी बात कही। भारत ने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अपने अनुभव साझा करने की पेशकश की। यह संकेत देता है कि भारत म्यांमार में स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और दीर्घकालिक शांति को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक मानता है।

हम आपको यह भी बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी महत्वपूर्ण मुलाकात की। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों की गतिविधियां, अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने साफ किया कि म्यांमार की स्थिरता और वहां शांति बहाली भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। अजित डोभाल के साथ हुई बातचीत में सामरिक सहयोग, खुफिया समन्वय और सीमा पार आतंकी नेटवर्क पर निगरानी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में व्यापार, संपर्क परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

देखा जाये तो म्यांमार के राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पूरा क्षेत्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला संकट और सुरक्षा चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। इस यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत और म्यांमार अपने संबंधों को केवल पारंपरिक पड़ोसी संबंधों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं। दुर्लभ खनिजों से लेकर सीमा सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं तक, दोनों देशों की बढ़ती निकटता आने वाले समय में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

कुल मिलाकर म्यांमार के साथ यह पूरी कूटनीतिक पहल मोदी सरकार की सक्रिय और दूरदर्शी विदेश नीति का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है। ऐसे समय में जब चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है, भारत ने म्यांमार के साथ सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को नई मजबूती देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने एक ओर जहां अपने पूर्वोत्तर की सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से उठाया, वहीं दूसरी ओर संपर्क परियोजनाओं, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के जरिए म्यांमार को भरोसेमंद सहयोग का संदेश भी दिया। यह कूटनीतिक सफलता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति और एशिया में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच उसकी मजबूत होती भूमिका भी साफ दिखाई देती है।

आज का इतिहास

1039 हेनरी तृतीय रोम के सम्राट बने।
1857 लखनऊ मैं बेगम हज़रत महल 1857 का विद्रोह नेतृव किया।
1674 अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स शहर में घोड़ों की दौड़ पर प्रतिबंध लगाया गया।
1845 मैक्सिको और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हुई।
1896 हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेटरोइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा।
1911 अलास्का के इंडियन क्रीक में सोना मिला।
1919 अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया।
1928 चीन के राष्ट्रपति हांग जोलिन की जापानी एजेंट ने हत्या की।
1929 जॉर्ज ईस्टमेन ने पहली टेक्निकलर मूवी का डेमो दिया।
1939 ओकलाहोम शहर में पहली बार खरीदारी करने वाली गाड़ी पेश की गई।
1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया।
1944 अमेरिकन आर्मी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया।
1959 सी. राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की।
1970 ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना।
1982 इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया।
1986 हेनरी फोर्ड ने अपनी कार की टेस्ट ड्राइव की।
1989 चीन की राजधानी बीजिंग में तियानानमेन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का हिंसक दमन किया गया।
1991 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश अल्बानिया में बनी।
2001 नेपाल के नव नियुक्त नरेश दीपेन्द्र का अस्पताल में निधन हुआ , इसके साथ ही नेपाल में ज्ञानेंद्र वीर बिक्रम शाह ने अपने भाई और बेटे की मौत के बाद सत्ता संभाली।
2003 डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमीलिया वेगा मिस यूनिवर्स-2003 बनीं।
2005 लालकृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया।
2006 यूगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की।
2007 चीन के उपप्रधानमंत्री हांग चू का निधन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डि सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया।
2015 घाना में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई।

आगामी दिनों में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के मायने

सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों के मंच के रूप में उभरे इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक पर देश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं। यह बैठक केवल विभिन्न दलों के नेताओं का एक औपचारिक जमावड़ा नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकता, उसकी रणनीति और भविष्य की राजनीतिक दिशा का महत्वपूर्ण संकेतक भी मानी जा रही है। ऐसे समय में जब देश की राजनीति लगातार नए समीकरणों और चुनौतियों से गुजर रही है, यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि विपक्ष यदि एकजुट होकर रणनीति बनाए तो वह सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन के भीतर कई मुद्दों पर मतभेदों की चर्चाएं भी सामने आईं। ऐसे में यह बैठक गठबंधन के भीतर विश्वास और समन्वय को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

बैठक का एक प्रमुख एजेंडा संसद के आगामी सत्रों में विपक्ष की संयुक्त रणनीति तय करना हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर विपक्ष किस प्रकार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, इस पर चर्चा होने की संभावना है। यदि गठबंधन इन मुद्दों पर एक स्वर में बोलने में सफल रहता है तो उसकी राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ सकती है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव भी बैठक के केंद्र में रह सकते हैं। सीटों के तालमेल, चुनावी रणनीति और साझा प्रचार अभियान जैसे विषयों पर सहमति बनाना गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। कई राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी रहे हैं। इसलिए यह बैठक इस बात की भी परीक्षा होगी कि गठबंधन अपने आंतरिक मतभेदों को कितनी कुशलता से संभाल पाता है।

राजनीतिक दृष्टि से यह बैठक विपक्षी नेतृत्व के प्रश्न पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि देश के सामने एक वैकल्पिक दृष्टि और भरोसेमंद नेतृत्व प्रस्तुत करना भी है। जनता केवल विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि समाधान और सकारात्मक एजेंडा भी देखना चाहती है।

सत्तापक्ष के लिए भी इस बैठक के निहितार्थ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक मजबूत और संगठित विपक्ष लोकतंत्र को अधिक

उत्तरदायी बनाता है। विपक्ष की सक्रियता सरकार को अपनी नीतियों और निर्णयों पर अधिक स्पष्टता तथा जवाबदेही के लिए प्रेरित करती है। इसलिए विपक्षी एकता का प्रश्न केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का भी विषय है।

इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक का महत्व उसके द्वारा पारित प्रस्तावों से कहीं अधिक इस बात में निहित होगा कि वह जनता के बीच कितना विश्वास पैदा कर पाती है। यदि बैठक से स्पष्ट रणनीति, मजबूत समन्वय और जनहित के मुद्दों पर ठोस दृष्टिकोण सामने आता है, तो यह विपक्ष के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। लेकिन यदि मतभेद और अस्पष्टता हावी रहती है, तो गठबंधन के सामने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती और बढ़ जाएगी। लोकतंत्र में सशक्त सरकार जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष भी है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक इसी कसौटी पर परखी जाएगी।

इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक केवल सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति या सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहने वाली है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ (टीएमसी) से जुड़े नेताओं पर हुए हमलों, पार्टी और सहयोगी दलों के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी तथा विपक्षी एकजुटता को लेकर उठ रहे सवालों के कारण टीएमसी का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है।

टीएमसी इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है। पश्चिम बंगाल में उसका मजबूत जनाधार है और राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। लेकिन कई अवसरों पर टीएमसी और गठबंधन के अन्य दलों, के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यदि विपक्षी एकता को मजबूत करना है तो इन अंतर्विरोधों पर खुलकर चर्चा आवश्यक होगी।

हाल ही में टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि किसी दल के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगता है, तो यह केवल उस दल का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का विषय बन जाता है। इसलिए संभावना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राजनीतिक हिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा भी उठे।

दूसरी ओर, गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के मुकाबले एक साझा राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने की है। यदि सहयोगी दल आपसी मतभेदों को सार्वजनिक रूप से बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा लाभ सत्तापक्ष को मिल सकता है। इसलिए बैठक में टीएमसी से जुड़े विवादों पर चर्चा होने के साथ-साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी गठबंधन केवल चुनावी गणित का नाम नहीं है। उसकी सफलता आपसी विश्वास, साझा कार्यक्रम और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। टीएमसी का मुद्दा यदि बैठक में उठता है तो उसका उद्देश्य किसी दल को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि गठबंधन की एकजुटता और विश्वसनीयता को मजबूत करना होना चाहिए।

इंडिया गठबंधन की बैठक इस बात की परीक्षा होगी कि क्या विपक्ष अपने आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी और संगठित राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। टीएमसी से जुड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चा इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष उतना ही आवश्यक है जितनी मजबूत सरकार, और यह बैठक उसी संतुलन को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में असल मुद्दे क्या होंगे?

बद्री नारायण

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। यहां धीरे-धीरे चुनाव का माहौल बनने लगा है। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए शुरू हुआ संग्राम, रामायण की पुनर्व्याख्या और सनातन की सनातनता पर विमर्श इसी का प्रतीक है। आगामी चुनाव में असल मुद्दे क्या होंगे, इस पर कुछ माह बाद कयास लगना शुरू होगा, पर इतना तो अभी से साफ है कि आगामी चुनाव 'मुद्दों के भीतर मुद्दों' का चुनाव होगा। छोटे-छोटे मुद्दे और लोगों की अलग-अलग अपेक्षाएं चुनाव में जरूर दिखाई देंगी, किंतु चुनाव का महावृत्तांत हिंदुत्व और विकास के इर्द-गिर्द विकसित होगा। वास्तव में, ये दोनों महज चुनावी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि पिछले दो दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से उभरे हुए सतत विमर्श हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे इन मुद्दों का सामना करना ही होगा और इन मुद्दों पर अपनी सोच व दृष्टिकोण जनता के सामने खुलकर रखनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति, भाषणों और कार्यशैली में तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों के धार्मिक उपयोग पर नियंत्रण, कुछ मंदिरों से जुड़े ऐतिहासिक विवादों और उनसे जुड़ी स्मृतियों को सामने लाने, तथा बुलडोजर नीति जैसे मुद्दों को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास एजेंडे को भी जमीन पर लागू करने का प्रयास किया और उसे प्राथमिकता दी। अत: किसी भी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा से टकराना है, तो उसे इन महावृत्तांतों के विमर्श की जद में शामिल होना ही होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में की गई विकसित भारत की परिकल्पना के तहत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं। पिछले साल महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दर्ज किया गया। सरकार ने अपनी विकास की गति को गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित रखा है। गरीबों को केंद्र में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की योजनाओं के लिए आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2017-18 में 18,674 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, जो बढ़कर 2025-26 में 34,504 करोड़ रुपये हो गया है। इस वृद्धि का असर जमीनी स्तर पर गरीब समूहों की

विकासपरक गतिशीलता में दिखाई पड़ेगा।

गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही स्टैंड-अप इंडिया योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना हुआ है। घर मुहैया कराने का अभियान भी राज्य में तेज हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30.69 लाख घरों के अलावा, वर्ष 2018 के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3.65 लाख घर समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को दिए गए हैं। इन योजनाओं ने न केवल गरीब परिवारों को रहने के लिए पक्की छत उपलब्ध कराई है, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का एहसास भी कराया है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी दशक में पूरी हुई हैं। इससे विकास, गतिशीलता और निर्यात को गति मिली है, जो किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने अपने उत्पादों को तो बढ़ाया ही है, उनके निर्यात में भी बेहतर परिणाम प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश भारतीय निर्यात में योगदान देने वाले राज्यों में पांचवां राज्य बनकर उभरा है। इस अवधि में राज्य के निर्यात में करीब 76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र की योजनाओं का बेहतर संचालन व राज्य की संपूरक विकास परियोजनाओं के संयुक्त प्रभाव के रूप में राज्य लगातार विकास का ढांचागत और मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर रचता जा रहा है। कृषि, सिंचाई, नारी सशक्तीकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन योजनाओं का जमीनी असर राजनीति में भी दिखेगा। विपक्ष इसे समझता है, इसलिए कांग्रेस व समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। वहीं, राज्य में विकास का विमर्श कहीं न कहीं हिंदुत्व की भावना से भी जुड़ गया है। ऐसे में, साफ लगता है कि आगामी विधान सभा चुनाव में विकास और हिंदुत्व महावृत्तांत के रूप में उभरेंगे। पक्ष और विपक्ष, दोनों को ही इन दो बड़े विमर्शपरक वृत्त में रहकर अपने विमर्श की रणनीति तैयार करनी होगी।

कर्नाटक में सीएम बदलना कांग्रेस के नजरिये में बदलाव

रशीद किदवई

कर्नाटक की राजनीति में महीनों से चल रही अटकलों, खंडन-मंडन और दिल्ली में हुई गुप्त बैठकों के सिलसिले पर 28 मई की सुबह तब विराम लग गया, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में अपने इस्तीफे की पुष्टि की। शनिवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही डीके शिवकुमार का कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। बीते कुछ वर्षों की राजनीति में मुख्यमंत्रियों को बदलने में भाजपा ने महारत हासिल कर ली है। इसके विपरीत, कांग्रेस का मॉडल बेहद धीमा और कशमकश से भरा होता है। कर्नाटक में ऐसा ही हुआ है। सिद्धारमैया को सम्मानजनक विदाई और उनकी जगह डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपा जाना कांग्रेस की इसी पारंपरिक शैली का हिस्सा है। अलबत्ता, यह एक नयी शुरुआत की ओर भी इशारा करता है। स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब उन मामलों में भी निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जहां पहले वह आम सहमति बनाने के नाम पर उन्हें लंबे समय तक लटकाये रखते थे।

पर पार्टी ने एक जमे-जमाये कद्दावर नेता को हटाकर कोई सियासी जोखिम तो मोल नहीं ले लिया? राजनीतिक पंडित इसे एक ऐसा सोचा-समझा जोखिम मान रहे हैं, जिसे लेना कांग्रेस के लिए अपरिहार्य भी हो गया था। कांग्रेस के लिए चुनौतियां 2023 में उसी दिन शुरू हो गयी थीं, जिस दिन उसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। उसे 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर जीत मिली थी, जो बीते कई दशकों में पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन था। पर उस जीत के भीतर एक अंतर्विरोध भी छिपा था। सिद्धारमैया के पास जनाधार और व्यापक सामाजिक गठबंधन था, जबकि डीके शिवकुमार संगठनात्मक ताकत से लैस थे और राज्य में शीर्ष पद के लिए उनकी सबसे मजबूत दावेदारी भी थी। ऐसे में, आलाकमान को समझौता करवाना पड़ा। इसके तहत सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री

की जिम्मेदारी मिली। दोनों के बीच सत्ता के रोटेशन को लेकर ढाई-ढाई साल का कोई समझौता हुआ या नहीं, इस बारे में भ्रम बना रहा।

अब जब अगले विधानसभा चुनाव में दो साल से भी कम का वक्त रह गया है, तब शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिद्धारमैया के समर्थक विधायकों को अपने साथ दिखाने की मानी जा रही है। लेकिन यहां पर एक पेच भी है। दरअसल, यह मान लिया जाता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में विधायक किसी न किसी गुट के स्थायी सदस्य होते हैं। पर हकीकत इससे अधिक जटिल है। कांग्रेस के विधायक अपेक्षाकृत अधिक लचीले, सतर्क और दिल्ली से मिलने वाले राजनीतिक संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय दिखाई देता है और चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, तब अधिकांश विधायक उसके साथ खड़े नजर आते हैं। पर जैसे ही उन्हें संकेत मिलने लगते हैं कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री की राजनीतिक उपयोगिता को तौलने लगा है, उनका व्यवहार बदलने लगता है।

हालांकि यह कहना मुनासिब नहीं कि सभी विधायक अचानक डीके शिवकुमार के समर्थक बन जायेंगे। पर अनेक विधायकों ने यह संकेत जरूर दिया है कि वे कांग्रेस के भविष्य की खातिर आलाकमान का फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। फिर भी सिद्धारमैया के लोकप्रिय जनाधार के बीच अपनी जगह बनाना शिवकुमार के लिए आसान नहीं। पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने वाली सिद्धारमैया की 'अहिंदा' राजनीति ने कांग्रेस को 2023 में ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी गारंटी योजनाएं आज भी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी हैं। ऐसे नेता को कार्यकाल के बीच में हटाने पर अगर कोई असंतोष पैदा होता है, तो उससे शिवकुमार कैसे निपटेंगे, यह देखने वाली बात होगी।

यह एक राज्य में केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के नजरिये में बदलाव की भी दास्तान है, जो चार मई के बाद और स्पष्ट होकर सामने आयी है। उस दिन दक्षिण भारत के सियासी कैनवास ने कांग्रेस को एक नयी दिशा दिखाई। केरल में कांग्रेस-नीत गठबंधन सत्ता में शानदार वापसी करने में सफल रहा। वहीं तमिलनाडु में विजय की टीवीके जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब कांग्रेस ने वहां अतीत की पुरानी यादों में खोये रहने के बजाय व्यावहारिक राजनीति को चुना, जिसके चलते पार्टी दशकों बाद राज्य में दो कैबिनेट मंत्रियों के साथ नयी सरकार का हिस्सा बनी।

दरअसल राहुल गांधी को अहसास हो गया है कि कांग्रेस दक्षिण भारत में चुनाव जीत सकती है, व्यावहारिक राजनीति के जरिये सरकारों में भागीदारी कर सकती है, वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन बना सकती है और युवा मतदाताओं से भी संवाद स्थापित कर सकती है। कर्नाटक की राजनीति आगे किस करवट बैठती है, यह तो वक्त बतायेगा, मगर संदेश साफ है। सिद्धारमैया ने अपनी पारी खेल ली है। अब बारी शिवकुमार की है। राहुल गांधी भी शायद लंबे अरसे के बाद ऐसे नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस को यह याद दिलाने के लिए तैयार हैं कि राजनीति में सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है।

जनता से वसूली गयी कट मनी वापस लौटाने लगे टीएमसी नेता

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के माथाभांगा इलाके से सामने आई घटनाओं ने ममता बनर्जी के शासनकाल में फैले भ्रष्टाचार और कट मनी के खेल की परतें खोल दी हैं। वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीणों और छोटे व्यापारियों को स्थानीय दबंगों तथा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को मोटी रकम देनी पड़ती थी। अब सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीणों को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलने लगी है। यह घटनाक्रम न केवल पुराने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस प्रकार आम लोगों का हक छीना गया था।

माथाभांगा के कई ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने, जमीन या मकान खरीदने बेचने अथवा व्यापार करने तक के लिए उन्हें कट मनी देनी पड़ती थी। आरोप है कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद यह वसूली और अधिक संगठित तरीके से शुरू हुई। गरीब परिवारों को धमकाया जाता था कि यदि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। कई लाभार्थियों से पंद्रह हजार से बीस हजार रुपये तक वसूले गए।

अब जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद माहौल बदला, तो ग्रामीण खुलकर सामने आने लगे हैं। जिन लोगों ने वर्षों तक डर के कारण आवाज नहीं उठाई, वह अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई जगहों पर देखा गया कि कट मनी वसूलने वालों के घर के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कई जगह कट मनी वसूलने वालों से मारपीट की खबरें भी आईं। कई जगह बड़ी मात्रा में नकदी जब्ती की रिपोर्टें भी सामने आईं। इसके बाद दबाव बढ़ने पर कई स्थानीय टीएमसी नेताओं और दबंगों ने कट मनी लौटानी शुरू कर दी है। माथाभांगा

के सुभाषपल्ली इलाके में आवास योजना के लाभार्थियों को उनकी रकम वापस मिल गयी है। वहीं पचागढ़ ग्राम पंचायत के फकीरेरकुठी गांव में ग्रामीणों को खुले मैदान में बुलाकर नकद राशि लौटाई गई।

देखा जाये तो यह दृश्य अपने आप में अभूतपूर्व था। गांव के स्कूल मैदान में विशेष सभा बुलाई गई, जहां लोगों को नाम पुकार कर पैसे लौटाए गए। जिन नेताओं पर अवैध वसूली के आरोप लगे, उनमें से कुछ फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में उनके परिवार के लोग सामने आकर ग्रामीणों को पैसा लौटाते नजर आए। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके के प्रभावशाली नेताओं ने वर्षों में लगभग अस्सी लाख रुपये तक की वसूली की थी। अब जनता के गुस्से और कानूनी कार्रवाई के डर से उन्हें रकम लौटानी पड़ रही है।

एक ग्रामीण ने बताया कि जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर उससे भारी रकम ली गई थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बाद में जब उसे पता चला कि लोगों को पैसे वापस मिल रहे हैं, तो उसने भी अपना नाम दर्ज कराया और आखिरकार उसे उसकी रकम लौटा दी गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी की सत्ता के दौर में बिना पैसे दिए कोई भी काम संभव नहीं था।

इसके अलावा, एक और दृश्य सामने आया है जिसमें माथाभांगा के घुघुमारी इलाके में रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर घोषणा की गई कि जिन लोगों ने कट मनी दी थी, वे पंचायत सदस्य के घर पहुंचकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं। यह दृश्य राज्य की राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत माना जा रहा है। स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि अब ग्रामीण डरने की बजाय खुलकर सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

इसी बीच नदिया जिले से सामने आई एक और घटना ने ममता बनर्जी सरकार के दौरान योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर कर दिया है। महिलाओं के लिए चलाई गई लक्ष्मीर भंडार योजना में एक सौ तिहत्तर पुरुषों के नाम लाभार्थियों की सूची में पाए गए। यह योजना केवल महिलाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि पुरुषों के नाम पर खाते बनाकर फरवरी से लगातार धन निकाला जा रहा था।

जिला प्रशासन ने इन नामों को सूची से हटाकर जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे खेल को किस तरह अंजाम दिया गया और कितनी राशि का गबन हुआ। राज्य सरकार ने भी विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और अन्य जिलों में भी पड़ताल शुरू हो गयी है।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मीर भंडार योजना में लाखों फर्जी लाभार्थी शामिल किए गए। उनका कहना है कि महिलाओं के नाम पर चलाई जा रही योजना में पुरुषों का पैसा लेना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूर्ववर्ती शासन में भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच चुका था। यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित घोटाले की ओर संकेत करता है।

बहरहाल, कूचबिहार और नदिया की ये घटनाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। जहां पहले सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए गरीबों को रिश्वत देनी पड़ती थी, वहीं अब वही लोग अपनी मेहनत की कमाई वापस पा रहे हैं। साथ ही योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का खुलासा यह साबित करता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। अब जनता खुलकर सवाल पूछ रही है और अपने अधिकारों के लिए सामने आ रही है।

भारत-अमेरिका संबंध: सिर्फ राजदूत की भूमिका तक सीमित नहीं हैं सर्जियो गोर

हरीश गुप्ता

वर्ष 2025 के अधिकांश समय में, भारत ने खुद को एक असहज स्थिति में पाया, जहां वह अमेरिका का रणनीतिक साझेदार होने के साथ-साथ वाशिंगटन से सार्वजनिक आलोचना का लगातार निशाना भी बनता रहा। चाहे वह भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद हो, व्यापार असंतुलन हो या टैरिफ विवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की तीखी टिप्पणियां लगभग नियमित हो गई थीं। फिर आए सर्जियो गोर। जनवरी 2026 में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभालने से बहुत पहले ही, गोर ने अपनी अहमियत का संकेत दे दिया था।

एक बेहद असामान्य कदम उठाते हुए, उन्होंने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने से कुछ महीने पहले ही अक्तूबर 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजनयिक हलकों में इस मुलाकात को इस बात का स्पष्ट संकेत माना गया कि गोर को ट्रम्प प्रशासन के उच्च स्तर तक असाधारण पहुंच प्राप्त थी। उनके आगमन के बाद से भारत-अमेरिका संबंधों के लहजे में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

वाशिंगटन की ओर से भारत की सार्वजनिक आलोचना लगभग समाप्त हो गई है, और उसकी जगह व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और रणनीतिक मामलों में सहयोग पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। राजनयिक और पर्यवेक्षक दोनों ही व्हाइट हाउस में गोर की अद्वितीय स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों में आई कई बाधाओं को दूर करने में सहायक मानते हैं। हाल के समय में अमेरिकी राजदूत सबसे चर्चित

दूतों में से एक बनकर उभरे हैं। कई राजनयिकों के विपरीत, जो बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप काम करते हैं, गोर ने लगातार मीडिया से बातचीत और पूरे भारत में व्यापक यात्राओं के माध्यम से अपनी सार्वजनिक छवि को बरकरार रखा है। उनका संपर्क नई दिल्ली से कहीं आगे तक फैला हुआ है,

जिसमें क्षेत्रीय नेताओं, व्यापारिक समूहों और नागरिक समाज के साथ बैठकें शामिल हैं। अब सबका ध्यान संबंधों के अगले बड़े सवाल पर केंद्रित है: कौन किससे पहले मुलाकात करेगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति ट्रम्प का निमंत्रण मोदी को व्हाइट हाउस दौरे के लिए दे दिया है, लेकिन नई दिल्ली ने इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है।

राजनयिक हलकों में कई लोगों का तर्क है कि प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रम्प को पहले भारत आना चाहिए, संभवत: आगामी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए। जैसे-जैसे यह बहस आगे बढ़ रही है, एक बात स्पष्ट होती जा रही है : भारत-अमेरिका संबंधों के वर्तमान चरण में गोर की भूमिका का महत्व कम नहीं आंका जा सकता।

अब अपनी हॉबी को ही बना सकते हैं करियर ऑप्शन

आज के समय में जॉब करना आसान नहीं रह गया है। यह काम तब और मुश्किल हो जाता है, जब किसी का प्रोफेशन और हॉबी अलग-अलग हो। जिसके कारण आजकल कई लोग जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वे उन जॉब्स से खुश नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए जॉब करना और अपने पैशन को फॉलो करके उसमें आगे जाना दोनों बहुत अलग बात हैं। फिर चाहे उसमे पैसे थोड़े कम क्यों न हो।

फोटोग्राफी, राइटिंग, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग समेत कई ऐसी हॉबी होती हैं, जिन्हे आप फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। सोचिये जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपकी हॉबी है, उसे आप अलग से समय निकाल कर करते हैं, अगर इसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आप भी अपनी हॉबी को करियर का रूप देना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए 7 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले रिसर्च करें

अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है रिसर्च। किसी भी हॉबी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता लगाना है कि क्या आपकी हॉबी फुल टाइम करियर बना सकती है या नहीं। उसमें जॉब और करियर के क्या अवसर हैं और उस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनुभव की जरूरत पड़ती है।

सही फीडबैक लें

कोई भी व्यक्ति अपने काम को जज नहीं कर सकता और न ही आपका परिवार या दोस्त आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गाइडेंस के लिए जरूरत होती है एक अनुभवी प्रोफेशनल की जो आपका मेंटर बने। हमेशा याद रखें कि काम शुरू करने से पहले अपनी हॉबी के बारे में अपने मेंटर से ईमानदार फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूलें।

शुरू से शुरुआत करें

यह बात पहले ही अपने मन में बैठा लें कि जब आप कोई करियर स्विच करेंगे तो हो सकता है कि आपको नीचे से ही शुरू करना पड़े। आप अपनी जॉब में फिलहाल ऊंची पोस्ट पर हों, लेकिन आपको नये करियर में नीचे से ही शुरू करना होगा। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लें।

पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल

आपके पुराने और नये करियर में भले ही कोई समानताएं न हों। लेकिन फिर भी हर जगह से हम कुछ न कुछ स्किल्स तो सीखने को मिलती ही हैं। ऐसी कई स्किल होती हैं, जो हर फील्ड में काम आती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल यहां भी काम आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सभी स्किल का इस्तेमाल अपने नये करियर में करें।

अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनें

अपनी हॉबी में करियर बनाने से पहले आप उस फील्ड से जुड़े लोगों से संपर्क बनाएं। अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं, एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको उस फील्ड में सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अपने काम को मोनेटाइज करें

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक बिजनेस टर्म है जिसका इस्तेमाल उन उद्यमियों के द्वारा किया जाता है जो फंडिंग की तलाश में होते हैं। आपको भी अपने लिए फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए आर्थिक सुविधा बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं रहेगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश करें। आप चाहे तो आपकी स्किल को ऑनलाइन सिखा सकते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर ले सकते हैं। या फिर खुद की वर्कशॉप भी लगा सकते हैं।

इस तरह बदले अपने पैशन को प्रोफेशन में

जब आपके मन में अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का विचार आए तो सबसे पहले अपने सभी हॉबी की लिस्ट बनाएं। मान लीजिये आपकी तीन हॉबी हैं। आपको लिखने का शौक हैं, फोटोग्राफी और पेंटिंग का भी शौक है। अब एक-एक हॉबी पर विचार कीजिए और उसके साथ कुछ दिन जी कर देखें। इससे आपको अपने आप ही मालूम हो जायेगा कि किस काम को लेकर आप ज्यादा बेहतर हैं और वह कार्य करते हुए आपको ज्यादा खुशी मिलती है।

सफलता के लिए हमेशा याद रखें...

किसी भी कार्य की सफलता के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए। कार्य को प्रारम्भ करने के पीछे हमारा भाव क्या है। हम क्या करना चाहते हैं इसका महत्व है। सफलता के लिए भगवान का सुमिरन कर कार्य करें। भगवान का ध्यान कर किए जाने वाले कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता। कुछ लोग भगवान की असीम कृपा से कम परिश्रम में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। संतों ने सफलता के 3 मंत्र बताए। पहला भगवान का स्मरण, दूसरा धैर्य तथा तीसरा परमार्थ की भावना जुड़ी होनी चाहिए।

प्रत्येक मंदिर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए और भीतर से पवित्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भी बाहर से स्वच्छ और भीतर से पवित्र होना चाहिए। फिर कोई लम्बी साधना करने की जरूरत नहीं। मां त्रिस्तरीय काम करती है। सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका परिपालन और उसका संघार करती है। अम्बा के 3 स्तर हैं, स्त्री शरीर अम्बा का ही अंश है। ऐसा मानकर उसका 3 स्तर पर सम्मान करना चाहिए। कन्या का सम्मान, धर्मपत्नी का सम्मान और मां का सम्मान। आनंद की अंतिम सीमा आंसू हैं। हम सबका जीवन फल होना चाहिए प्रेम। सत्य शायद हम चूक जाएं। करुणा छूट जाए लेकिन प्रेम बना रहे। यह जीवन का फल है।

स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर

यदि आप लेखन में दक्षता रखते हैं और आपको किताबें पढऩे में भी गहरी रुचि है तो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप अपने शौक को करियर का रूप भी दे सकते हैं। जो युवा लिखने-पढऩे के साथ मानवीय संवेदनाओं को पकड़ कर अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्षेत्र

विज्ञापनों के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स की सेवाएं विशेष तौर पर ली जाती हैं। अक्सर विज्ञापनों में ऐसे शब्दों या पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। ये सब स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग की ही उपज होते हैं। ऐसी रोचक बातों को जिंगल्स कहा जाता है।

बेशक स्क्रिप्ट राइटर का काम सिर्फ जिंगल लिखना ही नहीं होता बल्कि और कई चीजें हैं जो स्क्रिप्ट राइटर करते हैं लेकिन अधिकतर की शुरूआत जिंगल्स से ही होती है। जाहिर है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कहानियां और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है इसीलिए लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं देखी जाएगी।

कौशल

इसमें क्षेत्र में करियर बनाने के लिए छात्रों में रचनात्मकता का होना आवश्यक है। कम शब्दों में आपको उत्पादों की विशेषताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। विज्ञापनों के लिए ऐसी जिंगल्स की रचना करनी पड़ती है कि सुनते या पढ़ते ही वह ग्राहक के जेहन में आ जाए। वैसे कोई डिग्री कोर्स तो नहीं होता पर ये जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है।

कल तक विज्ञापन ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बनाए जाते थे लेकिन आज जो विज्ञापन आ रहे हैं वे ग्राहकों के संतोष के साथ उसकी खुशी और मनोरंजन को भी महत्व दे रहे हैं। मानवीय भावनात्मक पक्षों को छूते विज्ञापन न सिर्फ देर तक याद रहते हैं बल्कि मन पर भी गहरा असर छोड़ते हैं।

जिस भी भाषा में आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं उसका गहन ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक पुस्तकों को भी पढऩा चाहिए ताकि आपको विभिन्न लेखकों की शैली की जानकारी भी प्राप्त हो सके। साथ ही फिल्मों तथा धारावाहिकों की स्क्रिप्ट पर गौर करने की आदत भी डाल लें। इसके बाद आप स्क्रिप्ट लेखन में हाथ आजमाएं।

योग्यता

स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे अहम जरूरत रचनात्मकता की होती है जो पूर्णत- व्यक्ति की विश्लेषण और कल्पना क्षमता पर आधारित होती है लेकिन फिर भी इसके लिए पत्रकारिता का कोर्स कर लिया जाए तो बेहतर होता है। किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास करने के बाद पत्रकारिता में ग्रैजुएशन कर सकते हैं। जो छात्र ग्रैजुएशन कर चुके हैं वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता में एम.ए. भी कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
एमिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
इंडियन इंस्टी. आफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

लाभदायक करियर इमेज कंसल्टिंग

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरैंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के ढंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टैंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमैंट, पॉलिसी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनैस इंस्टी. भारत में इमेज कंसल्टैंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनैस प्रोग्राम संबंधी अनोखे पेशेवर कोर्स करवाता है। इस संस्थान की डायरैक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टैंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान की डायरैक्टर हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2009 में की। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफैशनल इंटरनैशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टैंट बन गईं। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, ''80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कौशल एक इमेज कंसल्टैंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।'' उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

पत्राचार शिक्षा से बदलती युवाओं की तकदीर

आज सभी विषयों में ग्रैजुएशन तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टीफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है। अधिकतर पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें सभी विषय-विधाओं के 10+2 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। उपग्रह संचार, लो पावर ट्रांसमीटर्स की सहायता एवं सूचना सुपर-हाइवेज के माध्यम से देश भर में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, सेवारत व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं।

अधिकांश विश्वविद्यालय मुद्रित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

नवीन जिंदल, पीसी पारेख के खिलाफ किया समन जारी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने सोमवार को उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है। कोर्ट ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। स्पेशल जज सुनेना शर्मा ने नवीन जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, पी सी पारेख, राकेश कुमार जिंदल, राम किशोर, एस के अग्रवाल और जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड को 17 जुलाई को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से जुड़ी सबसे विस्तृत और भारी-भरकम आरोप-पत्रों में से एक है। मामले की जांच सीबीआई ने की है, जिसने आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री शाह आज से त्रिपुरा दौरे पर

नई दिल्ली । भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 और 5 जून को त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत वह सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सहित अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हालात का आकलन करने वाले है। बताया जा रहा हैं कि दौरे के दौरान सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य सीमा पार गतिविधियों को रोकने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली क्षेत्र में पुलिस ने 18 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इसमें छह बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में इन लोगों को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है।

6 जून को भारत आ रहा हूं, एयरपोर्ट पर मिलो, हो सकता हूं गिरफ्तार

नई दिल्ली। मुझसे एयरपोर्ट पर मिलो ये मैसेज कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को भेजा। अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से लौटने वाले हैं। भारत आने से पहले उन्होंने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बार-बार परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे, इस विफलता के कारण शिक्षा मंत्री प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके ने कहा कि वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विरोध प्रदर्शन अहिंसक और संवैधानिक होगा।

आज से भारत दौरे पर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति

नई दिल्ली। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार से भारत के पांच दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच उनकी यह यात्रा भारत के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर विचार किया जाएगा। डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला के विदेश, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्रालयों के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी भारत आ रहे हैं। भारत और वेनेजुएला के संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है।

हौजरानी अग्निकांड मामले में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को घेरा

नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस घटना में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने जोर दिया कि जब तक अवैध निर्माण में सरकार, नगर निगम, डीडीए, फायर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की मिलीभगत समाप्त नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घटना स्थल का दौरा न करने को असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि पिछले तीन महीनों में यह चौथी बड़ी घटना है, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस टूटने के कगार पर

58 विधायकों ने ऋतुब्रत को बंगाल विस में विपक्ष का नेता बनाने की मांग की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उठा-पटक के बीच पार्टी के 58 बागी विधायकों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथीन बोस को पत्र सौंपकर ऋतुब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता मान्यता देने की मांग की। दिलचस्प यह है कि इस शक्ति प्रदर्शन के बावजूद बागी विधायकों ने पत्र में ममता बनर्जी को ही पार्टी की नेता और सभानेत्री बताया है, जिससे संकेत मिला है कि उनका विरोध सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बागी खेमे की ओर से दिए गए पत्र में संदीपन साहा, जावेद खान और शिउली साहा को उपनेता तथा अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार स्पीकर ने पत्र स्वीकार कर लिया है, हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हस्ताक्षरों का सत्यापन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर जल्द फैसला हो सकता है।

तृणमूल में मौजूदा संकट की शुरुआत विपक्ष के नेता पद के लिए वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में भेजे गए एक पत्र से हुई थी। आरोप लगा कि उस पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस और सीआईडी जांच कर रही है तथा कई विधायकों से पूछताछ की जा चुकी है।

इसी विवाद के बाद ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद कई विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सामने आए और बागी खेमे का आकार लगातार बढ़ता गया। इसके

साथ ही तृणमूल में संभावित विभाजन और नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। बागी विधायक अरुणाभ सेन ने कहा, मैं आज भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानता हूं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को कभी नेता नहीं माना और न ही मानूंगा। हमने विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनकर स्पीकर को पत्र सौंप दिया है।

अब निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिकी हैं। यदि 58 विधायकों के समर्थन का दावा वैध पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

बुधवार को ऋतब्रत बंद्योपाध्याय 58 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ विधानसभा पहुंचे। इसके बाद से नई तृणमूल के गठन और विधानसभा में नए शक्ति संतुलन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्टों में जिन नेताओं के नाम संभावित नए गुट के साथ जोड़े जा रहे हैं, उनमें पूर्व मंत्री और हावड़ा मध्य के विधायक अरूप राय, डोमजूर के तापस माइती, महेशतला के शुभाशीष दास, कुलपी की बर्णाली धारा, केशपुर की शिउली साहा, सामसेरगंज के मोहम्मद नूर आलम, हरिहरपाड़ा के नियामत शेख, लालगोला के अब्दुल अजीज, भगवानगोला के रियात हुसैन, सूती के इमानी विश्वास, रघुनाथगंज के आक्रुज्जामान, खड़गपुर के दिनेन राय और सुजापुर की सबीना यासमीन प्रमुख हैं। इसके अलावा समर मुखोपाध्याय, रथीन घोष, संदीपन साहा, चंद्रनाथ सिन्हा और समीर जना समेत कई अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं।

बुधवार को कथित बागी गुट के कई नेताओं ने दावा किया कि उन्हें टीएमसी के 80 में से अधिकतर विधायकों का समर्थन हासिल है। इस मुद्दे पर टीएमसी विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने पत्रकारों से कहा, हमें सटीक संख्या नहीं पता, लेकिन बाहर से सुनने में आ रहा है कि 59 हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं। मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं। राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि दो-तिहाई से अधिक विधायकों के समर्थन के साथ एक अलग गुट बनाने की तैयारी चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि नए गुट से जुड़े बताए जा रहे नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वे अब भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे और निर्णय प्रक्रिया को लेकर असंतोष रखते हैं।

इस वजह से इसे सीधे नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई के बजाय संगठन के भीतर शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं नए गुट की ओर से भी किसी औपचारिक घोषणा, नेतृत्व संरचना या राजनीतिक रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में बंगाल की राजनीति में जारी घटनाक्रम पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर न केवल राज्य की सत्ता बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति की दिशा पर भी पड़ सकता है।

टीएमसी में विद्रोह के बाद सभी संगठन भंग

कोलकाता। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत पश्चिम बंगाल में अपनी सभी समितियों और अपने सहयोगी संगठनों को तत्काल भंग करने की घोषणा 3 जून को की। यह निर्णय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ते विद्रोह की खबरों के बीच आया है, जिसमें कई विधायकों के महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में अनुपस्थित रहने और आंतरिक तनाव के कारण हाल ही में दो विधायकों के निष्कासन की खबरें सामने आई हैं। एक्स पर जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियाँ, साथ ही इसके सभी सहयोगी संगठन, तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए जाएँगे। पार्टी ने यह भी कहा कि वह आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन समीक्षा और हर स्तर पर संगठनात्मक मूल्यांकन सहित एक व्यापक आंतरिक प्रक्रिया का संचालन करेगी। एआईटीसी ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर, मूल संगठन और सभी सहयोगी संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, एआईटीसी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य संगठन को नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।

वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल कांग्रेस का एक और पार्षद गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं पर भ्रष्टाचार और वसूली के मामलों को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बंगाल में एक टीएमसी पार्षद की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के एक और पार्षद को वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पुलिस ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोप में केएमसी के तृणमूल पार्षदों की कुल गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गरफा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मंगलवार रात को कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 106 के पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को गिरफ्तार किया। उन पर स्थानीय प्रमोटरों और व्यापारियों से धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना

पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को मिलेंगे 3,000

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पहले चरण में 28.25 लाख लाभार्थियों को 3,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। इसे बंगाल की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना माना जा रहा है।

योजना के पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खातों में आज से सीधे 3,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस योजना से लगभग दो करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा।

बंगाल की पहली भाजपा सरकार की इस अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन समारोह में सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद रहीं। योजना का उद्घाटन कार्यक्रम राज्य के सभी ब्लॉकों, नगरपालिकाओं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया।

उद्घाटन के तुरंत बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में चयनित 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इसी तरह कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी 100 लाभार्थियों को ये पत्र दिए गए। सूत्रों के अनुसार, संबंधित उपमंडल अधिकारियों (एसडीओ), बीडीओ और नगरपालिका प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इस वित्तीय मदद से वे अपने घरेलू खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में %अन्नपूर्णा योजना% का एलान किया गया था। यह तृणमूल कांग्रेस सरकार की %लक्ष्मी भंडार% योजना की जगह लेगी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपए मिलते थे।

योजना के तहत पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को 90 दिनों का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।

खेल

प्रमुख समाचार

40 दिनों में भारत के खिलाफ 12 मैच खेलेगा न्यूजीलैंड

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (एनजेडसी) ने बुधवार को अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र 2026/27 का कार्यक्रम जारी कर दिया। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण भारत का न्यूजीलैंड दौरा है, जिसे मेजबान देश के इतिहास के सबसे बड़े द्विपक्षीय क्रिकेट दौरों में से एक माना जा रहा है। भारतीय टीम 22 अक्तूबर से एक दिसंबर 2026 तक न्यूजीलैंड में रहेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 12 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं। करीब 40 दिनों तक चलने वाला यह दौरा पांच प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा।

भारत का दौरा पांच मैचों की टी20 सीरीज से शुरू होगा। पहला और दूसरा टी20 क्रमश: 22 और 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेले जाएंगे। इसके बाद तीसरा टी20 27 अक्तूबर को वेलिंगटन में होगा, जबकि चौथा मुकाबला 30 अक्तूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। पांचवां और अंतिम टी20 मैच एक नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में आयोजित होगा।

टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें पांच मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी। पहला वनडे चार नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला सात नवंबर को वेलिंगटन में और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। चौथा और पांचवां वनडे क्रमश: 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई (टौरंगा) के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे।

दौरे का समापन दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगा। पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के प्रतिष्ठित बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा। दूसरा और अंतिम टेस्ट 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में आयोजित होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 304 अंक फिसला निफ्टी 23,406 पर बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में बुधवार को दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान निचले स्तर से रिकवरी के बावजूद बाजार लाल निशान में बंद हुआ। पीएसयू बैंक और वित्तीय शेयरों में मजबूती ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाने में अहम भूमिका निभाई। निफ्टी50 बुधवार को 77.95 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,405.60 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 303.67 अंक या 0.41 प्रतिशत टूटकर 74,346.17 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, दोनों प्रमुख इंडेक्स दिन के निचले स्तर से कुछ हद तक संभलने में सफल रहे। एसबीआई सेक्यूरीटिस के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड सुधीप शाह के अनुसार, आने वाले समय में निफ्टी के लिए तुरंत रेजिस्टेंस (बाधा स्तर) 23530 से 23550 के बीच रहेगा। अगर निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से बना रहता है, तो इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है।

मई में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के हाई पर

नईदिल्ली। मई में भारत के सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ छह महीने के हाई पर पहुंच गई। यह जानकारी बुधवार को जारी एक मासिक सर्वे के मुताबिक, मजबूत मांग, नए ग्राहकों के जुड़ने और नए कारोबार में लगातार सुधार के चलते सर्विसेज में रफ्तार देखने को मिली। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मई में बढ़कर 59.8 पर पहुंच गया, जो अप्रैल में 58.8 था। यह पिछले साल नवंबर के बाद सेवा क्षेत्र में विस्तार की सबसे तेज रफ्तार को दर्शाता है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स एक सवाल के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें कंपनियों से पूछा जाता है कि पिछले महीने की तुलना में उनकी कारोबारी गतिविधियां कैसी रहीं। पीएमआई में 50 से ऊपर का स्तर विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का स्तर गिरावट को दर्शाता है।

सरकार पीएनजी कनेक्शन के लिए लाएगी राष्ट्रीय केंद्रीकृत पोर्टल

नईदिल्ली। सरकार पीएनजी कनेक्शन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने पर काम कर रही है। इसके आने के बाद उपभोक्ताओं को अलग-अलग गैस कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे एक ही वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नए सिस्टम के तहत गैस वितरण कंपनियों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कनेक्शन देना होगा। सरकार इस पोर्टल के जरिए कंपनियों के काम की रियल टाइम निगरानी भी करेगी। इसके अलावा, उपभोक्ता ऑनलाइन मैप के जरिए यह भी देख सकेंगे कि उनके घर के पास पाइपलाइन उपलब्ध है या नहीं। यह बदलाव मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण किया जा रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60% आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है।

भारत समेत कई देशों पर अमेरिका का नया टैरिफ वार

वाशिंगटन। अमेरिका ने भारत सहित अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि कई देशों ने कथित जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। इसी आधार पर भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि जांच के दौरान 54 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी पाई गईं, जिन्होंने जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं किया। इस सूची में भारत, चीन, वियतनाम, ताइवान और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर भी 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है।

रिजर्व बैंक ने खोली अर्थव्यवस्था के ढोल की पोल

सनत जैन

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े विभिन्न संकेतक यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार और उसके समर्थकों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देने वाली वास्तविकताएं एक अलग कहानी कह रही हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है। एक समय देश अपनी जरूरत का लगभग 18 प्रतिशत कच्चा तेल और गैस स्वयं उत्पादित कर लेता था। शेष 82 प्रतिशत आयात करना पड़ता था। अब आयात पर निर्भरता और बढ़ गई है। कच्चे तेल, गैस, उर्वरक और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक सामान और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ता असंतुलन चिंता का विषय है। यदि किसी देश का आयात लगातार निर्यात से अधिक रहेगा तो अंतत: विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। भारत का व्यापार घाटा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में वृद्धि दिखाई नहीं दे रही। जिस गति से आयात बढ़ा है, उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़ पाया है। इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ रहा है। डॉलर और युआन जैसी मुद्राओं के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। जिसके कारण आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। पिछले वर्षों में सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए, आलोचकों का मानना है, इन अभियानों का प्रभाव औद्योगिक

उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में कहीं पर दिखाई भी दिए तो वो भी बहुत नीचे स्तर पर हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात आधारित उपभोग अर्थव्यवस्था को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता का एक दूसरा कारण देश में बढ़ता कर्ज है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार उधार लेकर खर्च बढ़ा रही हैं। निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड आधारित उधारी में तेजी से वृद्धि हुई है। जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास का आधार उत्पादन और आय की बजाय कर्ज बनने लगे, तो यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जाती। जब खर्च करने के लिये पैसे नहीं होंगे, तो आर्थिक विकास कैसे संभव है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है। इन तीनों घटनाओं ने छोटे और मध्यम उद्योगों को गहरा झटका दिया। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था, आज भी वह उबर नहीं पाया है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। लोगों की आय कई वर्षों से सीमित है। आय की तुलना में अधिक तेजी से जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है।

शेयर बाजार को लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बताया जाता रहा। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निकासी की जा रही हैं। यदि विदेशी निवेश कम होता है, घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता, तो आर्थिक विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर एशिया के कई शेयर बाजार अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल रही है। ऊर्जा आयात महंगा होता है, तो उसका असर परिवहन, कृषि, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पड़ता है। अंतत: इसका भार आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। वर्तमान स्थिति की तुलना 1991 के आर्थिक संकट से होने लगी है। भारत के पास उस समय की तुलना में वर्तमान में कहीं अधिक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और विकसित वित्तीय बाजार मौजूद हैं।

'मुख्यमंत्री किसान संवाद' कार्यक्रम में किसानों से किया आत्मीय संवाद

खेती केवल आजीविका नहीं, हमारी संस्कृति और पहचान का आधार: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित 'मुख्यमंत्री किसान संवाद' में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है।कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

जिले में जनमानस को मिले गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं: डॉ. रमन सिंह

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने के मद्देनजर डॉक्टरों से संवाद किया तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोत्तरी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिले में जनमानस को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 3 करोड़ 56 लाख 70 हजार रूपए की लागत से निर्मित जिला चिकित्सालय भवन के ऊंचाई विस्तार कार्य का लोकार्पण किया गया है तथा 2 करोड़ 86 लाख रूपए की लागत से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया है। जिससे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सशक्त अधोसंरचना मिलेगी। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में जिला चिकित्सालय में पानी भरने की समस्या होती थी। जिसे दूर करने के लिए उन्नयन कार्य किया गया है। तीन फीट ऊपर होने के बाद ऊंचाई बढ़ गई है, जिससे पानी भरने की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों एवं जीवन दीप समिति की लगातार चिंता से स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध डॉक्टरों की टीम है। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। स्वास्थ्य मापदण्डों में निरंतर सुधार करते हुए अधोसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, आधुनिक और प्रभावी बनाने जिला चिकित्सालय हेतु सीटी स्कैन, डिजिटल एक्स-रे एवं डेंटल एक्स-रे मशीनों उपलब्धता के लिए कहा।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिला चिकित्सालय में प्रवेश करते ही एक नएपन का एहसास हुआ। बारिश के दिनों में यहां पानी भरा जाता था।

सुशासन तिहार: मौके पर ही दूर हो रही हैं जनता की तकलीफें: राजस्व मंत्री वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निराकरण के लिए सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम छेरकापुर में एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शिविर के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 55 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुंचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान,समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के विकास हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का जमीनी स्तर पर समाधान करना है। %विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी% के तहत राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है।

छत्तीसगढ़ के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती

- 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
- प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजीडेंट के पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन से प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में, 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों—दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी (जशपुर), जांजगीर-चांपा और कबीरधाम- में प्राध्यापक , सह-प्राध्यापक , सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजीडेंट के कुल 149 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि *15 जून 2026* निर्धारित की गई है । इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://monitoringcell.cgdme.in/mpas पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । जारी विज्ञापन के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों (जैसे- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन आदि) के लिए संविदा पदों का वर्गीकरण किया गया है।

खेत बचाओ अभियान: चौपालों में मिल रही लाभकारी खेती की सीख

रायपुर। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसानों को वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती की जानकारी देने के लिए चलाया जा रहा 'खेत बचाओ अभियान' ग्रामीण क्षेत्रों में नई जागरूकता पैदा कर रहा है। कृषि विभाग के इस विशेष अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद कर रहे हैं तथा उन्हें कम लागत और अधिक उत्पादन वाली खेती के गुर सिखा रहे हैं।

1 जून से 15 जून तक संचालित इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पहाड़ लुड़ेग में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और कृषि नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी गई।

चौपाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम-आशा योजना और सुगंधित जवांफूल धान की खेती के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। कृषि अधिकारियों ने बताया कि सुगंधित जवांफूल चावल की बाजार में लगातार मांग बढ़ रही है और इसके उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। यही वजह है कि किसानों को इसका रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। किसानों को हरी खाद, ढैंचा, बीजी कल्चर, गोबर खाद और जीवामृत के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा रासायनिक लागत कम करने के उपाय बताए गए। साथ ही फसल प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों की जानकारी भी साझा की गई। कृषि विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर मिलने से किसानों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। विभाग का मानना है कि ऐसे अभियान किसानों को आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती के समन्वय से जोड़कर उत्पादन बढ़ाने और आय में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

कथित सुशासन की जगह-जगह भद पिट रही : बैज

रायपुर। तथाकथित सुशासन की असली पोल सुशासन त्यौहार में खुल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनता को भ्रमित करने तथा अपनी नाकामियों से पर्दा डालने सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद अब अधिकारियों को धमकाने, चमकाने पर उतर आये है। ढाई साल के सरकार जनता से दूर हो चुकी है। सुशासन त्यौहार के नाम पर जब जनता के बीच जा रहे तब जनाक्रोश को दबाने अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे है। मंत्री दयालदास बघेल मंच से शराब तस्करी के लिए पुलिस को दोषी ठहरा रहे है, तो विधायक रोहित साहू पटवारी को धमका रहे है, सांसद भोजराज नाग अधिकारी को निपटाने की धमकी दे रहे है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल शराब के खुलेआम बेचने पर आक्रोशित है, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह कलेक्टर, एसपी को धमका रहे, विधायक तहसीलदार से मारपीट कर रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, उस पर से सरकार बेशर्मी पूर्वक सुशासन का त्यौहार मना रही है। विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ महिलाओं से महतारी वंदन का फार्म भरवाये, 18 लाख पीएम आवास देने का फर्जी दावा किये, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा किये।

गौठानों का नाम बदलकर शुरू करने मजबूर हुई : शुक्ला

रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा आरंभ किए गए गौठान योजना का नाम बदलकर 1400 गौधाम के नाम से संचालित करने के निर्णय को भाजपा सरकार का यू-टर्न है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार अंततः गौठानो का नाम बदलकर शुरू करने मजबूर हुई। ढाई साल बाद ही सही यह सरकार जागी तो सही। जो लोग राजनैतिक दुर्भावनावश गौठान का विरोध कर रहे थे, विगत ढाई वर्षो में स्वयं की कोई योजना ला नहीं सके, अब गौ-वंशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए वापस उन्हें गौठानो का आश्रय लेना पड़ रहा है। चुनाव के समय जो गौ-माता के नाम पर वोट मांगते हैं, वही भाजपाई उन्हें अब आवारा पशु कह रहे हैं। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता और दुर्भावनापूर्ण निर्णय से 10 हजार से अधिक गौठानो में ताले लगे और किसके चलते सैकड़ो की संख्या में गाय सड़क पर कुचलकर मार दी गई उस पाप के लिए यह सरकार ही जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि गौठान योजना बंद करने का दुष्परिणाम सड़कों पर दिख रहा है, सड़कों पर मवेशियों की मौत और रोज-रोज हादसों हो रहे। भाजपा सरकार की उपेक्षा, पूर्वाग्रह और दुर्भावना के चलते ही गायें सड़कों पर कुचली जा रही हैं।

अवैध रेत खनन रोकने में सरकार असफल: ठाकुर

रायपुर। राज्यपाल महोदय द्वारा अवैध रेत खनन को लेकर खनिज सचिव को बैठक के बाद कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अवैध रेत खनन रोकने में सरकार असफल हो गई है। बार-बार शिकायत के बावजूद अवैध रेत खनन रुक नही रहा है। अब राज्यपाल महोदय को खनिज सचिव को लोकभवन बुलाकर रेत खनन रोकने आवश्यक निर्देश देने पड़ रहे है।इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार की अवैध रेत खनन को रोकने गम्भीर नही थी। जिम्मेदार अधिकारी अवैध रेत खनन को रोकने के निर्देशों का पालन नही कर रहे थे। जिसके चलते पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन माफिया सक्रिय है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अवैध रेत खनन रोकने को लेकर जनता और विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है। लेकिन सरकार के कान में जूं नही रेंग रही थी। अवैध रेत खनन माफिया द्वारा लगातार आतंक फैलाया जा रहा है। ग्रामीणों के साथ मारपीट, माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष लगातार हो रहे है। माफियों को इतनी छूट दे दी गई है कि वो शमशान घाट में दफन शव को भी उखाड़ कर रेत निकाल रहे थे। सरकार मूकदर्शक बनकर चुप बैठी रही है।

मोदी निर्मित महंगाई राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है: वर्मा

रायपुर। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और आर्थिक संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन भाजपा सरकार जवाबदेही से भाग रही है, आवश्यक वस्तुओं में अनियंत्रित मूल्यवृद्धि से हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, महंगाई मोदी निर्मित आपदा बन चुकी है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 984 रु. के पार है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में सीधे तीन गुना से अधिक बढ़ा दिया। पेट्रोल-डीजल के दाम में पिछले 15 दिन में 12 रू. की बढ़ोत्तरी हुयी है। पेट्रोल 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 105 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के पार हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंका, दिया सिर्फ धन्ना सेठों को मौका। हाल ही में आई 'ऑक्सफैम' की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास देश की मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति। विडंबना यह है कि नीचे के इन 50 प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी 64 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल राजनैतिक नौटंकी: वंदना

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किये गए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन को केवल राजनैतिक नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा की भाजपा सरकार ज़ब से बनी है राजनैतिक प्रचार और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जतन मात्र करती है उसे जनता की समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में भी हर गुरुवार को जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ढाई साल में आधा दर्जन गुरुवार को भी मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिले। भाजपा सरकार् ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों को नियमित बैठने की घोषणा किया वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी बहुत जल्दी उबाऊ कॉल सेंटर में तब्दील होगा फिर बंद हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा की राज्य में सभी विभागों सरकारी काम कितने दिन में होगा हर काम को करने के लिए समय अवधि निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया गया था और वह आज भी लागू है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के दफ्तरो में लगाया गया सिटीजन चार्टर का बोर्ड तक हटा दिया गया। किसी दफ्तर में कोई काम नहीं होता। राज्य में सरकार और सरकार की योजनाए विज्ञापनो में ही दिखती है।

समाधान का सशक्त मंच बन रहा सुशासन तिहार

रायपुर। जनपद पंचायत रायगढ़ के भगोरा क्लस्टर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर ग्रामीणों के लिए समाधान और जनकल्याण का प्रभावी मंच बनकर उभरा। 21 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं, मांगें और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं। शिविर में कुल 675 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण कर लोगों को तत्काल राहत प्रदान की गई।

शिविर में जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। शिविर केवल शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ वितरण का भी केंद्र बना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रतनी राठिया एवं सुखमति राठिया को डबरी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि मकरध्वज को जॉब कार्ड वितरित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा तीन दिव्यांग हितग्राहियों को वॉकिंग स्टिक प्रदान की गई। खाद्य विभाग के माध्यम से पांच हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच हितग्राहियों को पक्के आवास की चाबी सौंपी गई। वहीं दो हितग्राहियों को सामाजिक पेंशन स्वीकृति तथा सात हितग्राहियों को श्रम कार्ड प्रदान किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तिलगा, टारपाली एवं संबलपुरी के पांच विद्यार्थियों तथा हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संबलपुरी, तिलगा, टारपाली एवं सपनई के सात विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सात ग्राम पंचायतों को पेयजल गुणवत्ता की जांच हेतु फील्ड टेस्ट किट प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।

नल जल योजना के पाइप चोरी के 8 आरोपी गिरफ्तार, 50 हज़ार के पाइप बरामद शिविर में आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेवाओं का लाभ उठाया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनजागरूकता पर विशेष जोर, अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व आम नागरिकों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों का त्वरित समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाना है।

किसान क्रेडिट कार्ड बना भरोसे का सहारा

रायपुर। खेती के लिए समय पर पूंजी की उपलब्धता किसानों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। लंबे समय तक कई किसान खेती-किसानी के खर्च पूरे करने के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना उनके लिए मजबूत आर्थिक संबल बनकर उभर रही है। गरियाबंद जिले में सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में किसानों को इस योजना से जोड़ने की पहल ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

विकासखंड गरियाबंद के ग्राम आमदी में आयोजित शिविर में ग्राम भीरालाट के किसान खिलावन राम तथा ग्राम हसौदा के किसान सरजूराम और सिराधर ध्रुव को किसान क्रेडिट कार्ड सह पासबुक वितरित की गई। किसान सिराधर ध्रुव के लिए यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि खेती को आत्मनिर्भर बनाने का नया माध्यम है। उनका कहना है कि अब उन्हें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिल सकेगा, जिससे खेती की जरूरतों के लिए निजी उधारदाताओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को फसल ऋण, खाद-बीज की खरीद, सिंचाई, कृषि यंत्रों के रखरखाव और अन्य कृषि कार्यों के लिए सरल ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। पासबुक के माध्यम से लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कृषि निवेश बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना किसानों के लिए आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती का नया आधार बनती जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.